



30
महीने

नये कदम बढ़ते कदम

उपलब्धियों की एक झलक
जून 2014 से दिसम्बर 2016 तक

कृषि उन्नति, हमारी प्राथमिकता



सत्यमेव जयते

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार



श्री राधा मोहन सिंह
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री



श्री एस.एस. अहलुवालिया
कृषि एवं किसान कल्याण
और संसदीय कार्य राज्यमंत्री



श्री परशोत्तम रूपाला
कृषि एवं किसान कल्याण
राज्यमंत्री



श्री सुदर्शन भगत
कृषि एवं किसान कल्याण
राज्यमंत्री

स्वस्थ धरा, खेत हरा

नये कदम बढ़ते कदम

उपलब्धियों की एक झलक
जून 2014 से दिसम्बर 2016 तक

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद



कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार



**कृषि, सहकारिता
एवं
किसान कल्याण विभाग**



सॉयल हेल्थ कार्ड



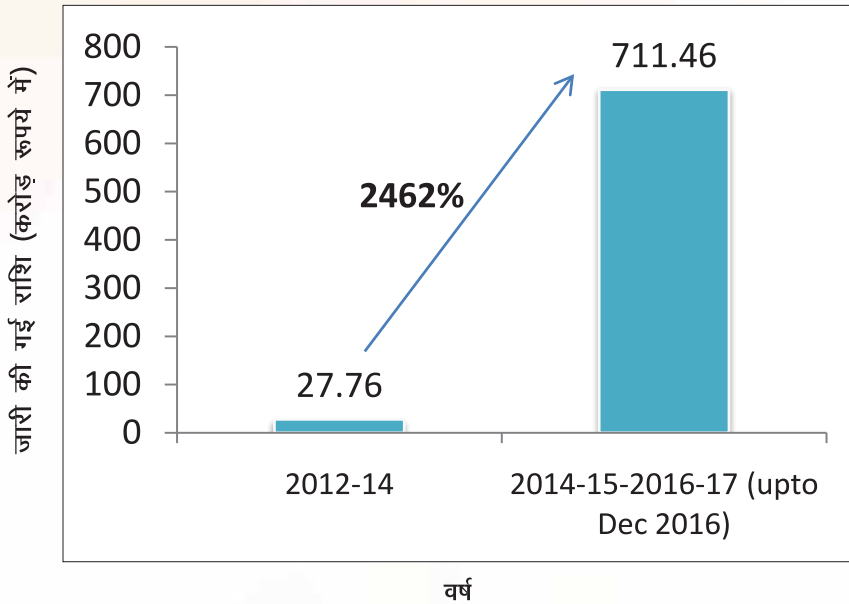
सॉयल हेल्थ कार्ड - अनेक लाभ

- ◆ उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर जानकारी ।
- ◆ बेहतर भूमि प्रबंधन पद्धतियों को अपनाया जाना ।
- ◆ अधिक पैदावार के लिए फसल विविधीकरण को अपनाया जाना ।
- ◆ 2.29 करोड़ नमूने एकत्र किए गए हैं जिनसे 11.45 करोड़ कार्ड बनाए जा रहे है ।
- ◆ किसानों को 4.15 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित किए जा चुके है ।
- ◆ आय दोगुनी करने के लिए कृषि लागत में कमी ।



सॉयल स्वास्थ्य प्रबंधन

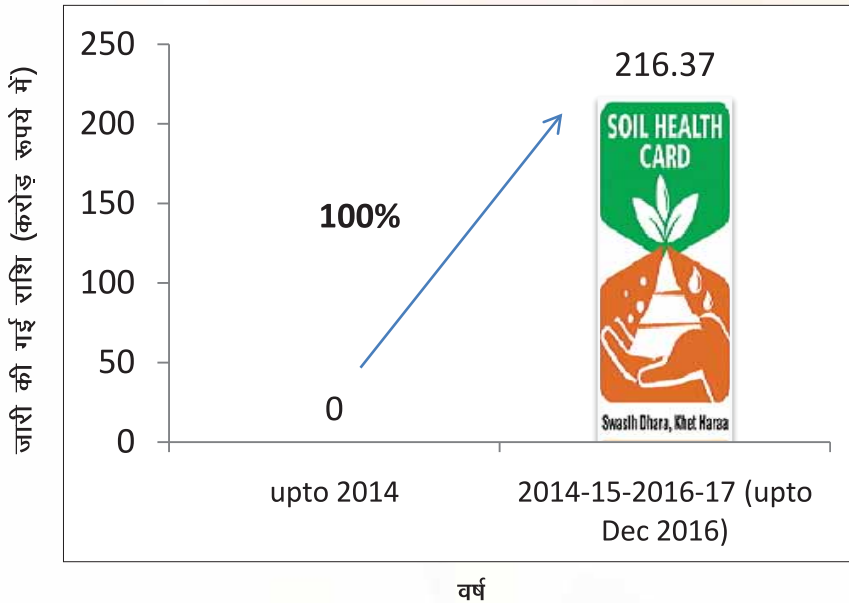
सॉयल स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि



2014-15 में राज्यों को 711.46 करोड़ रुपए जारी किए गए जो 2012-13 और 2013-14 के दौरान जारी किए गए 27.76 करोड़ रुपए का 26 गुना है।

सॉयल हेल्थ कार्ड

सॉयल हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि

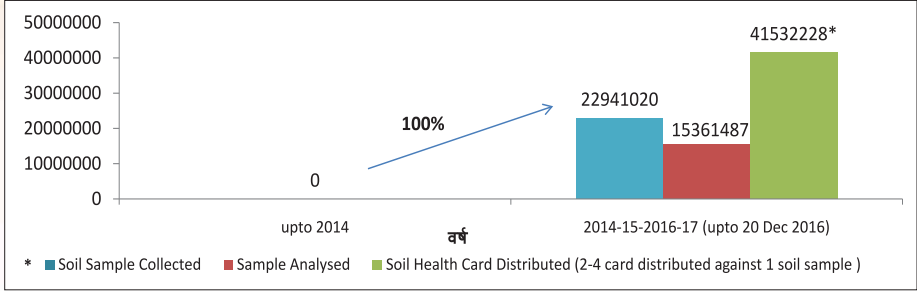


सॉयल हेल्थ कार्ड योजना के अन्तर्गत 2014-15, 2015-16 और 2016-17 (दिसम्बर 2016 तक) के दौरान 216.37 करोड़ रूपए जारी किए गए।

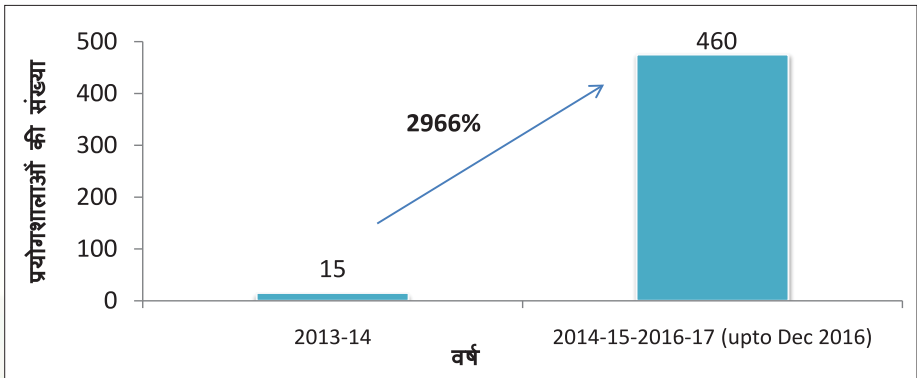
- ◆ सॉयल हेल्थ कार्ड की मदद से किसान मुख्य पोषक तत्वों, सूक्ष्म पोषक तत्वों तथा उर्वरक की फसलवार सिफारिश प्राप्त कर सकते हैं।
- ◆ किसान सुझाये गए उपाचारी उपाय जान सकते हैं जिनका उपयोग मृदा स्वास्थ्य में सुधार करने और बेहतर तथा अधिक उपज प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

सॉयल हेल्थ कार्ड योजना

सॉयल हेल्थ कार्ड योजना की स्थिति



मंजूर की गई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं (अचल+चल+मिनी प्रयोगशालाएं)



- ◆ फरवरी 2015 में सॉयल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की गई।
- ◆ 460 सॉयल परीक्षण प्रयोगशालाएं मंजूर की गईं।
- ◆ देश में सभी भू जोतकों के लिए प्रत्येक दो वर्ष में सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे।

परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)



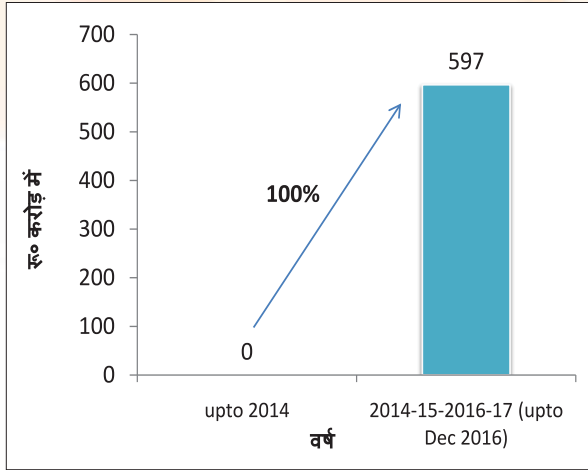
सिक्किम: भारत का पहला जैविक राज्य



- ◆ क्लस्टर निर्माण, किसानों को संगठित करने हेतु पीजीएस प्रमाणीकरण, जैविक कृषि में भूमि के अन्तरण, वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना, जैविक उत्पादों की लेबलिंग अथवा ब्रांडिंग।
- ◆ प्रत्येक क्लस्टर के लिए 120000 रु० अधिकतम सहायता पर विपणन के लिए जैविक उत्पाद के संग्रहण और परिवहन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- ◆ क्लस्टर के प्रत्येक किसान को 3 वर्ष की अवधि के दौरान 50,000 रु० प्रति हैक्टे० की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। 20 हैक्टेयर के 10,000 जैविक क्लस्टरों को विकसित किया जायेगा ताकि 3 वर्षों के दौरान 2 लाख है० तक प्रमाणित क्षेत्र को कवर किया जा सके। अभी तक 9,186 क्लस्टर बनाए जा चुके हैं।
- ◆ सरकार द्वारा परम्परागत संसाधनों, अनुकूल पर्यावरण हितैषी कम लागत प्रौद्योगिकियों और अधिक लाभ आदि के उपयोग के साथ जैविक खेती को बढ़ावा दिया जायेगा।

परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)

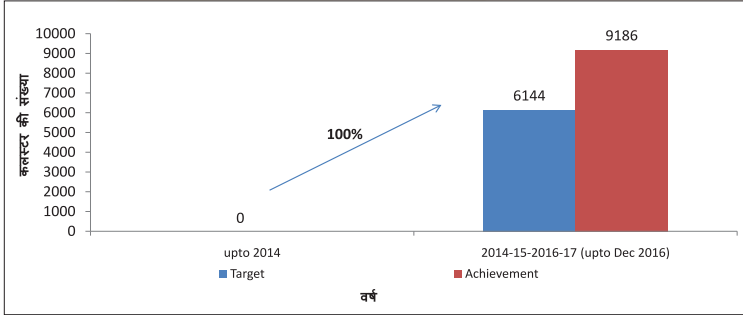
पीकेवीवाई के तहत आवंटित निधि



- ◆ तीन वर्षों में 10,000 क्लस्टर (20 हैक्टेयर प्रत्येक) विकसित करना और तीन वर्षों में 2 लाख हैक्टेयर तक प्रमाणित क्षेत्र को बढ़ाना।
- ◆ 50,000 प्रति किसान/हैक्टेयर की दर पर प्रत्येक 20 हैक्टेयर क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण।

परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) की स्थिति

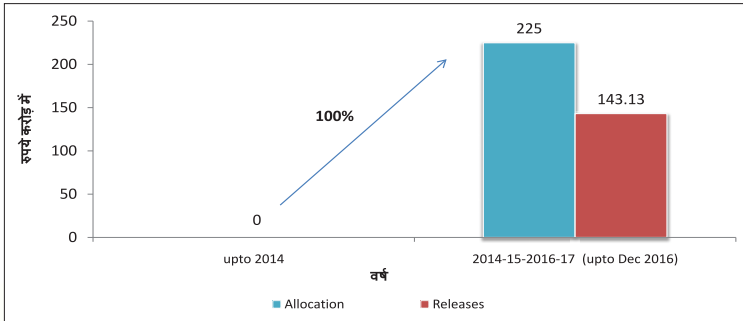
पीकेवीवाई के तहत वार्षिक कार्य योजना में कलस्टर निर्माण
(लक्ष्य और उपलब्धियां संख्या में)



दिसम्बर, 2016 तक 10000 समूहों के लक्ष्य की तुलना 9186 समूह मंजूर किये गये।

पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडी)

पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु एमओवीसीडी के तहत आवंटन और निर्मुक्त निधि



- ◆ पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों को निधि निर्मुक्त करने का उद्देश्य उपभोक्ताओं के साथ किसानों के संपर्क के लिए मूल्य श्रृंखला मोड में प्रमाणित जैविक उत्पादन का विकास करना है।
- ◆ योजना वर्ष 2015-16 से 3 वर्षों के लिए 400 करोड़ के परिचय के साथ शुरू की गई थी।
- ◆ वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 के दौरान 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किये जाने का लक्ष्य है।

नीम लेपित यूरिया

- ◆ भारत सरकार ने मई, 2015 से 100% नीम लेपित यूरिया उत्पादन करने हेतु इसे विनिर्माताओं के लिए अनिवार्य बनाया है।
- ◆ दिसम्बर 2015 से आयातित यूरिया भी नीम तेल से 100% लेपित हो रहा है।
- ◆ अब मंडी में उपलब्ध कुल यूरिया नीम लेपित है।
- ◆ खरीफ 2016 पहला मौसम था जिसमें उपयोग किया गया कुल यूरिया नीम लेपित था।
- ◆ सरकार ने एमओपी की लागत को 5000 रूपए प्रति टन और डीएपी की लागत को 2500 रूपए प्रति टन तक घटाया है।
- ◆ सरकार ने डीएपी के 50 किग्रा बोरे की कीमत में 125 रूपए एवं एमओपी के 50 किग्रा बोरे पर 250 रूपए कीमत में कमी की है।



- ◆ प्रत्येक दाना नीम तेल से लेपित होता है, जो मृदा में यूरिया के घुलन दर को कम कर देता है और इस प्रकार फसलों के लिए नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाता है।

राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-एनएएम)



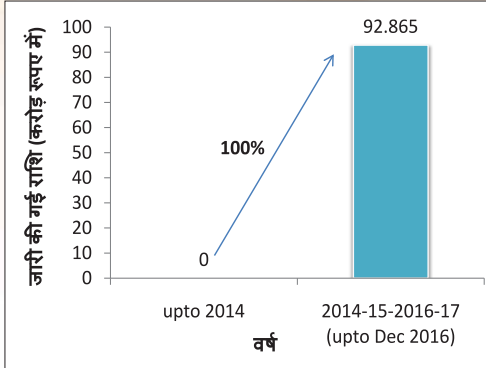
- ◆ पूरे देश में एक कॉमन ई-प्लेटफार्म के माध्यम से 585 थोक एपीएमसी मंडियों को जोड़ने के लिए 200 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटन से राष्ट्रीय कृषि मंडी (एनएएम) का 1 जुलाई, 2015 को अनुमोदन किया गया था।
- ◆ 14 अप्रैल, 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 राज्यों की 21 मंडियों में बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के 125वें जन्म दिवस पर ई-एनएएम का पायलेट लांच किया।
- ◆ ई-एनएएम कुछ निम्नलिखित सुधारों के साथ जुड़ी हुई स्कीम है।
 - ◆ पूरे राज्य में एकल लाईसेंस वैध होना।
 - ◆ मंडी शुल्क की एकल बिंदु वसूली
 - ◆ मूल्य पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निलामी का प्रावधान।

प्रगति

- ◆ 14 राज्यों को उनकी 399 मंडियों को ई-एनएएम के साथ जोड़ने के लिए सिद्धांत रूप से अनुमोदन दिया गया।
- ◆ ई-एनएएम पर ट्रेडिंग के लिए जिंसों का आंकलन किए जाने को सरल बनाने के लिए 69 जिंसों के लिए कॉमन ब्यापार योग्य पैरामीटर विकसित किए गए हैं।
- ◆ 10 राज्यों की 250 मंडियों को ई-एनएएम के साथ एकीकृत कर दिया गया है।
- ◆ 16.12.2016 तक 6,13,890.61 लाख रुपये के 31,13,494.35 टन कृषि उत्पाद का कारोबार e-NAM पर हो चुका है। साथ ही 8,55,839 किसानों, 59,155 व्यापारियों और 30,790 कमीशन एजेंटों को e-NAM प्लेटफार्म पर पंजीकृत किया जा चुका है।

कृषि विपणन

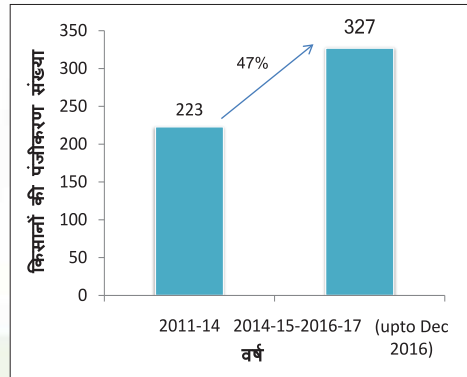
राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-एनएएम) निधि निर्मुक्त स्थिति



सरकार ने देश में ई-मंडी को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त राशि जारी की है।

लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएससी) द्वारा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का पंजीकरण

किसानों के संगठीकरण के लिए 47 प्रतिशत कुल वृद्धि के साथ 2011-14 के दौरान 223 एफपीओ की तुलना में 2014-16 के दौरान 327 एफपीओ को पंजीकृत किया गया।

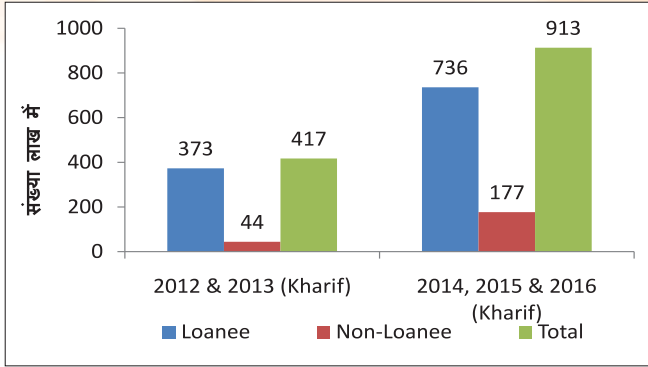


ज्वाइंट लाएबिलिटी ग्रुप को वित्तीय सहायता

2007 से 2014 तक (7 वर्षों में) 6.7 लाख ज्वाइंट लाएबिलिटी समूहों की तुलना में 2014 से 2016 (2.5 वर्षों में) 18.21 लाख समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। 2007 से 2014 तक (7 वर्षों में) रु. 6630 करोड़ की संचित उपलब्धियों की तुलना में 2014 से सितम्बर 2016 (2.5 वर्षों) तक रु. 18,006 करोड़ की राशि की वित्तीय सहायता संयुक्त देय समूहों को प्रदान की गयी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

फसल बीमा योजना के तहत कवर किसान



ज्यादा से ज्यादा ऋणी तथा गैर ऋणी किसानों ने फसल बीमा योजना को अपनाया। यह इस योजना की सफलताएं हैं

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमबीएफवाई) की मुख्य विशेषताएं:

- ◆ सभी अनाजों, तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें शामिल हैं।
- ◆ एक मौसम एक दर— खरीफ के लिए 2 प्रतिशत, रबी के लिए 1.5 प्रतिशत और वार्षिक बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत अधिकतम है।
- ◆ फसल उपज के सभी जोखिमों—फसल बुआई के पूर्व खड़ी फसल तथा फसल कटाई के बाद के जोखिम शामिल।
- ◆ ओलावृष्टि, भूस्खलन और जलभराव से हुए नुकसान के लिए प्रत्येक खेत स्तर पर क्षति का आकलन करना।
- ◆ फसल कटाई से अधिकतम 14 की अवधि में चक्रवात/चक्रवात वर्षा एवं बेमौसम बारिश के विशेष खतरों के कारण हुए फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति भी प्रत्येक खेत स्तर पर।
- ◆ प्राकृतिक आपदा के कारण संरक्षित बुआई के लिए बीमित राशि 25 प्रतिशत तक का भुगतान।
- ◆ विगत खरीफ 2015 में 309 लाख किसान 23 राज्यों में फसल बीमा योजना में कवर किये गए थे जिनमे से 294 लाख ऋणी और 15 लाख गैर ऋणी थे। खरीफ 2016 में लगभग 366.64 लाख किसान कवर हुए हैं जिनमें से 264.04 लाख ऋणी किसान और 102.60 लाख गैर ऋणी किसान हैं।



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

Soil Health Card Scheme - Swasth Dhara, Khat-Haraa
To protect the soil health and to advice the farmers on appropriate doses of fertilizer and manures, Govt. of India is promoting Soil Health Card (SHC) for all farmers free of cost indicating status of soil with respect to 12 parameters including macro & micro-nutrients.

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana
With a view to provide efficient and judicious use of water for all, farm, Govt. has launched Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana which will ensure food & nutrient rich from water source to farm level by implementing farm irrigation through Drip and sprinkler system.

eNAM (Electronic National Agriculture Market)
Government has set up an electronic marketing platform for enabling farmers to sell their produce at the best possible price across the country. 500 regulated markets across country are targeted to link to this platform by March 2018.

Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Government of India
Krishi Bhawan, Rajendra Prasad Road, New Delhi (110001)
www.agri-insurance.gov.in

Shri Narendra Modi
Hon'ble Prime Minister of India

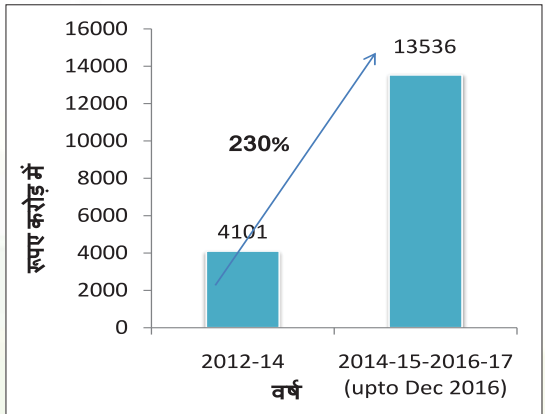
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
PRADHAN MANTRI FASAL BIMA YOJANA

Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Government of India

Kisan Call Centre : 1800 180 1551
सिंचन जागरी... सुरक्षा सरकार की

पीएमएफबीवाई के तहत जारी निधि

- ◆ बीमा विवरण वाली पावती रसीद के साथ पॉकेट साइज फोलियो जो पॉलिसी कागजात के रूप में भी कार्य करेगा।
- ◆ यह पहली बार रबी 2016 से किसानों के बीच पावती वितरित की जा रही है।

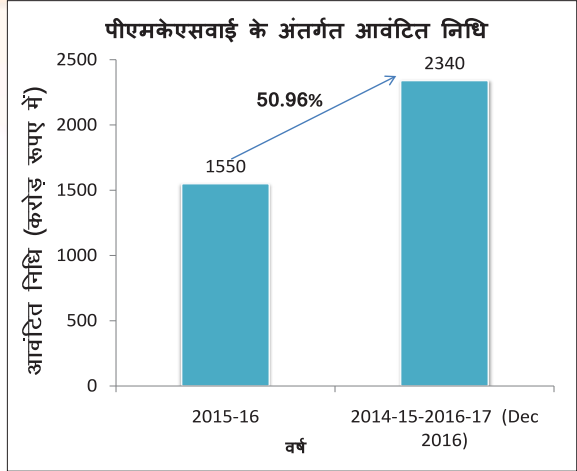


2014-17 के दौरान पीएमएफबीवाई के तहत पर्याप्त निधि जारी की गई।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

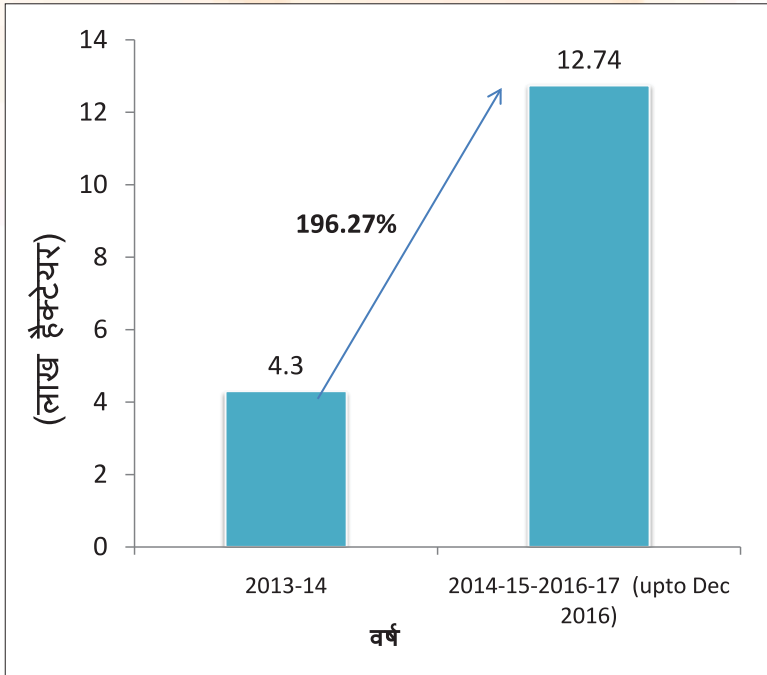
किसान कैसे लाभ उठा पाएंगे?

- ◆ ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है जो लगभग समाप्त होने वाली है ताकि किसान शीघ्र लाभ उठा सकें।
- ◆ किसान बेहतर जल संचयन तकनीकों का उपयोग कर सकेंगे।
- ◆ किसान ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग कर सकेंगे।
- ◆ किसान अपने जिला कृषि/बागवानी अधिकारी से ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीकों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- ◆ किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नं०-1800-180-1551 से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
- ◆ 2016-17 के दौरान पीएमकेएसवाई-“प्रतिबूंद अधिक फसल” को आवंटित निधियां 2340 करोड़ रुपए हैं और सूक्ष्म सिंचाई के तहत 8 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य है। 30.12.2016 तक राज्यों को 1512.65 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
- ◆ परिशुद्ध सिंचाई प्रणाली अर्थात ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के तहत शामिल किया गया कुल क्षेत्र 2.36 लाख हैक्टेयर है और संरक्षित सिंचाई के लिए 27835 हैक्टेयर की क्षमता वाली 18750 जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया।



प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

पीएमकेएसवाई के तहत क्षेत्र



- ◆ सूक्ष्म अर्थात ड्रिप एवं स्प्रिंकलर के क्षेत्र में उचित बढ़ोत्तरी



बागवानी विकास (एनएचबी)



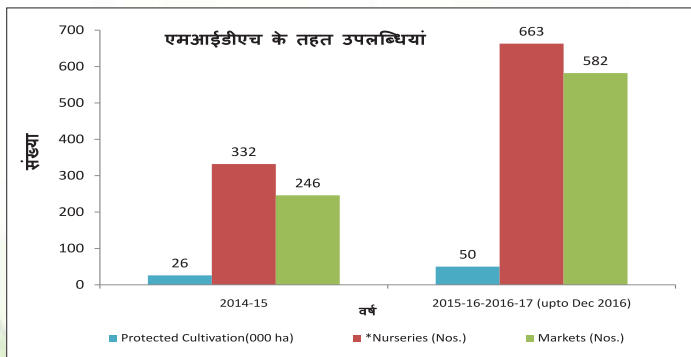
शीत भंडारण योजना

- ◆ 217.79 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता के साथ 144 शीत भंडारण परियोजनाओं को सहायता दी गई।
- ◆ 7.14 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त शीत भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया।

बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी विकास एवं विस्तार

- ◆ प्रौद्योगिकी के अंतरण हेतु 547 परियोजनाओं/कार्यक्रमों को वित्त पोषित किया गया।
- ◆ उच्च गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री के उत्पादन हेतु 1206 नर्सरियों को प्रत्यायित किया गया।

बागवानी विकास



पिछल दो वर्षों में एमआईडीएच के विभिन्न घटकों के अंतर्गत विशेष उपलब्धियां

बागवानी विकास



केन्द्रीय कृषि मंत्री ने 23 अगस्त 2014 को केसर पार्क का पुलवामा, जम्मू एवं कश्मीर में शिलान्यास किया।

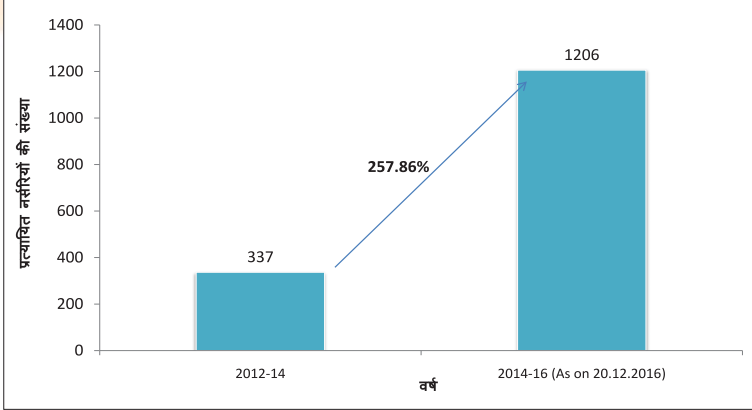
केसर पार्क

- ◆ 24.45 करोड़ रुपये की कुल लागत से पम्पोर पुलवामा (जम्मू और कश्मीर) में केसर पार्क स्थापित करने का कार्य एनएचवी को सौंपा है। पार्क में गुणवत्ता नियंत्रण लैब, निर्यात प्रोत्साहन कार्यकलाप और ई-निलामी केंद्र की सुविधा होगी।
- ◆ पार्क का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। प्रदान की गई प्लांट और मशीनरी स्थापित करने हेतु तैयार है।
- ◆ पार्क के वर्तमान केसर मौसम के दौरान शुरू हो जाने की संभावना है।



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी)

फल पौध नर्सरियों का प्रत्यायन एवं श्रेणी निर्धारण



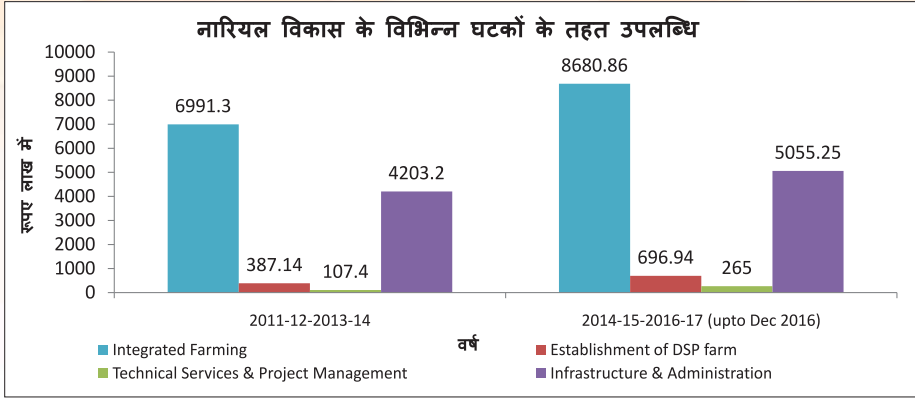
वर्ष 2012-14 की तुलना में 2014-16 के दौरान प्रत्यायित नर्सरियों में 2.5 गुणा वृद्धि

बागवानी विकास

जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री का पैकेज

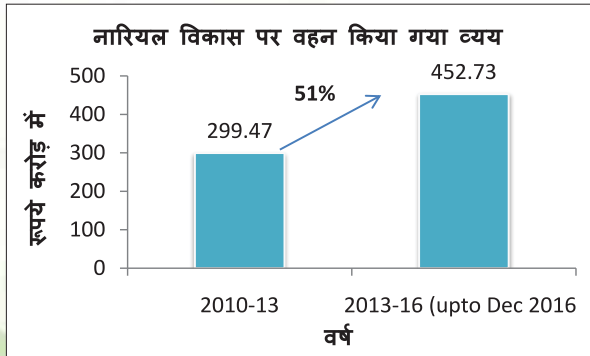
- ◆ जम्मू-कश्मीर में क्षतिग्रस्त बागवानी क्षेत्रों के पुनरुत्थापन और बागवानी विकास के लिए 07.11.2015 को 500 करोड़ रूपए के विशेष पैकेज की घोषणा की गई।
- ◆ जम्मू-कश्मीर सरकार ने 2016-17 से 2018-19 के लिए 500 करोड़ रूपए की अपनी 3 वर्ष की कार्य योजना प्रस्तुत की।
- ◆ आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने एमआईडीएच लागत मानदंडों के लिए एकमुश्त छूट का अनुमोदन किया:
 - 460 रूपए प्रति पौध की अधिकतम लागत पर रोपण सामग्री का आयात।
 - 9.8 लाख प्रति हैक्टेयर की दर पर फोर वायर टेरिल सिस्टम का आयात।
 - रोपण सामग्री के प्रावधान हेतु 90 प्रतिशत की दर पर राज्य सहायता को बढ़ाया गया।
 - सीसीईए निर्णय के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति 08.12.2016 को जारी की गयी है।
 - 24/08/2016 को 47.89 करोड़ रूपए (भारत सरकार का हिस्सा) जारी किया गया। शेष निधियां जारी कर दी जाएंगी।

नारियल विकास बोर्ड



- ◆ भारत विश्व में नारियल उत्पादन एवं उत्पादकता में प्रथम स्थान पर आ गया है। नारियल क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता क्रमशः 1.97 मिलियन हैक्टेयर, 20.439 बिलियन गिरी और प्रति हैक्टेयर 10345 गिरी पहुंच गई है।
- ◆ वर्ष 2016—17 के शुरुआत से ही भारत नारियल तेल का निर्यात मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका को करने लगा है, जबकि हम पिछले वर्ष तक इन्हीं देशों से नारियल तेल का आयात कर रहे थे।
- ◆ 18 एकल नारियल बीज उद्यानों एवं 86 लघु नारियल नर्सरियों की स्थापना की गई। 361 जैविक खाद्य इकाइयों की स्थापना की गई।

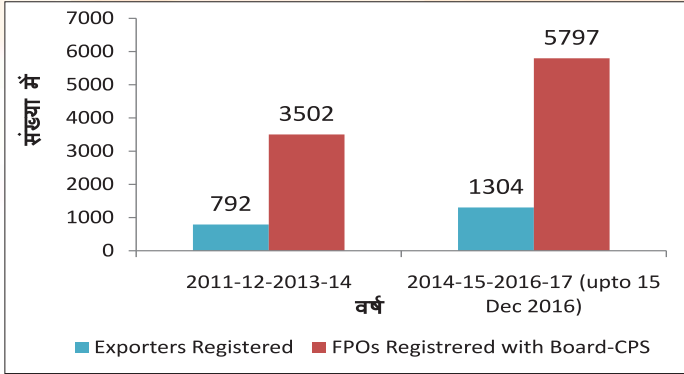
- ◆ 7356 नारियल उत्पादक सोसाईटियों, 646 नारियल उत्पादक संघों एवं 57 नारियल उत्पादक कंपनियों की स्थापना की गई।
- ◆ 2314 नीरा तकनीशियन को प्रशिक्षित किया गया।
- ◆ नए रोपण के तहत 9163 हैक्टे. को लाया गया है।
- ◆ “नारियल वृक्ष मित्र” के



तहत 392013 नारियल पाम पेड़ पर चढ़ने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

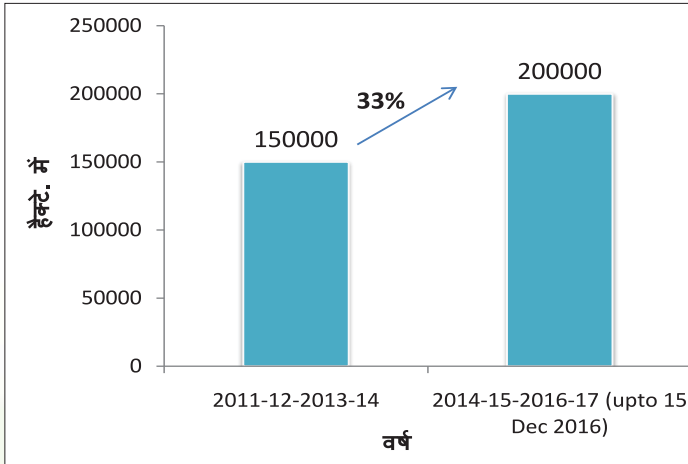
नारियल विकास बोर्ड

सीडीबी योजनाएं - वास्तविक उपलब्धियां



- वर्ष 2011-14 की तुलना में वर्ष 2014-16 के दौरान नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) के निर्यातक व एफपीओ पंजीकरण में पर्याप्त वृद्धि।

पुनरोपण एवं पुनोद्धार क्षेत्र (हेक्टेयर में)



- वर्ष 2011-14 और 2014-16 के दौरान नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) के पुनरोपण एवं क्षेत्र पुनरोद्धार में 33 प्रतिशत की वृद्धि।

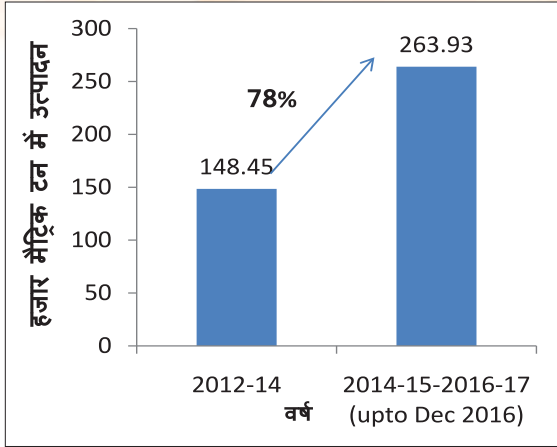
मधुमक्खी पालन

- ◆ राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन बोर्ड (एनबीबी) द्वारा वर्ष 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन में 11862 किसानों/मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षित किया गया है।
- ◆ शहद उत्पादन वर्ष 2012-13 में 72,300 एमटी से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 94,500 एमटी (अनुमानित) हो गया है।
- ◆ शहद एकत्र करने के लिए अच्छे ग्रेड के प्लास्टिक के बर्तनों के लिए डिजाइन्ड तकनीकी मानक।
- ◆ 10.62 लाख कॉलोनियों सहित 6361 मधुमक्खी पालकों/मधुमक्खी पालन एवं मधु सोसाइटियों/फर्मों/कंपनियों आदि को पंजीकृत किया गया (दिसम्बर 2016 तक)



राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी)

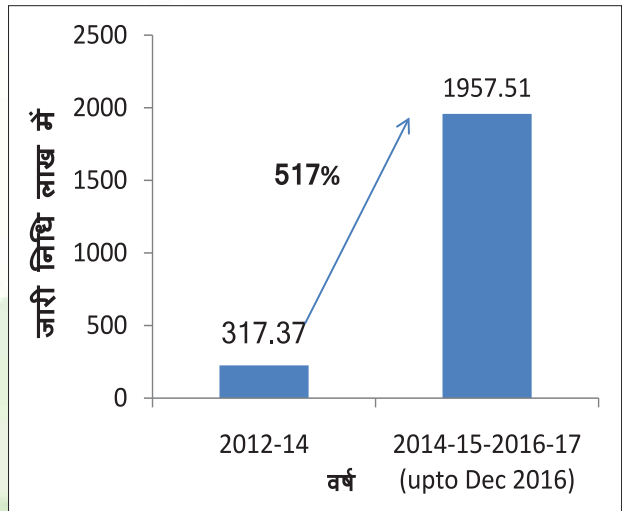
शहद उत्पादन



राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा मधुमक्खी पालकों/किसानों को सुविधा पहुंचाने देने के लिए वर्ष 2012-13 और 2013-14 की तुलना में वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान बजट आवंटन में वृद्धि के साथ-साथ 78 प्रतिशत मधु उत्पादन में वृद्धि

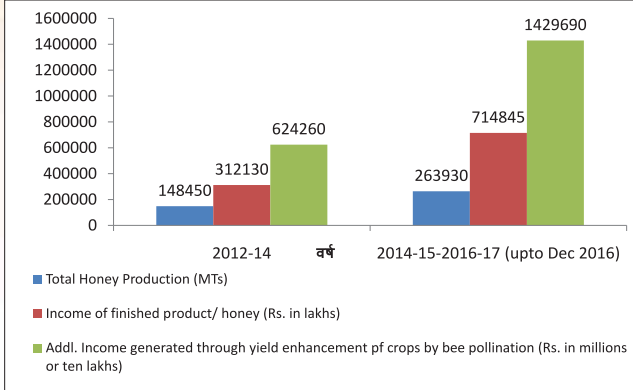
मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए जारी/आवंटित निधियां

वर्ष 2012-14 की तुलना में वर्ष 2014-15-2016-17 के पिछले 3 वर्षों में मधुमक्खी पालन के लिए बजट में लगभग 517 प्रतिशत की वृद्धि।



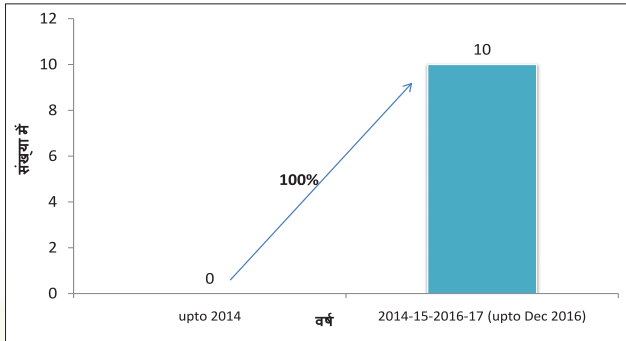
राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी)

मधुमक्खी पालन विकास के माध्यम से सृजित अतिरिक्त आय



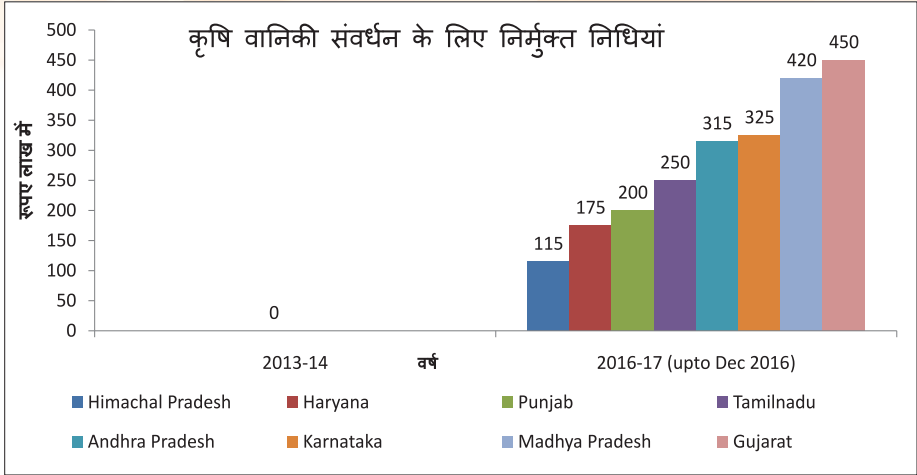
मधुमक्खी पालकों के साथ-साथ किसानों ने अतिरिक्त आय प्राप्त की।

समेकित मधुमक्खी पालन विकास केन्द्र, उत्कृष्टता केंद्रों (आईबीडीसी/सीओईएस) की स्थापना/स्वीकृति



2015-16 एवं 2016-17 (दिसम्बर 2016 तक) के दौरान एनबीबी द्वारा 10 आईबीडी, हरियाणा (बागवानी विभाग, कुरुक्षेत्र), दिल्ली (आईएआरआई पूसा), बिहार (केवीके पिपराकोठी), पंजाब (पीएयू लुधियाना), मध्य प्रदेश (केवीके, मोरेना), उत्तर प्रदेश, (आईआईवीआर, वाराणसी), मणिपुर (सीएयू, इम्फाल), उत्तराखंड (केवीके, देहरादून), जम्मू एवं कश्मीर (एसकेवीएसटी, श्रीनगर) और तमिलनाडु (टीएनएयू, कोयम्बटूर) में एक आईबीसी स्थापित/अनुमोदित की गई।

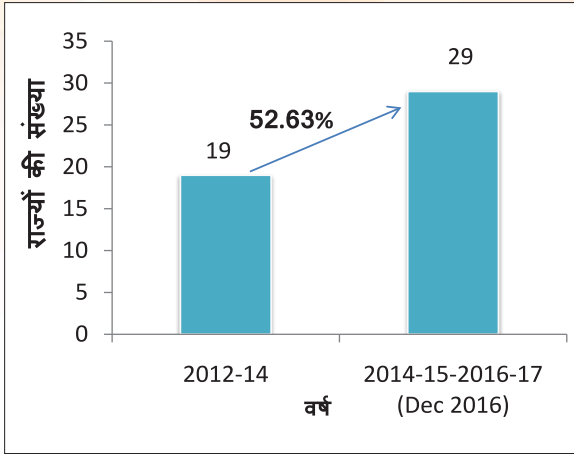
कृषि वानिकी उपमिशन



- ◆ किसानों की आय को बढ़ाने और जलवायु अनुकूलता के लिए राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति तैयार की गई।
- ◆ वर्ष 2016-17 के दौरान “हर मेंड़ पर पेड़” के लक्ष्य के साथ एक समर्पित योजना “राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना” की शुरुआत की गई।
- ◆ वर्ष 2016-17 में 75 करोड़ रुपए के केन्द्रीय हिस्से का बजट आवंटित।
- ◆ कृषि वानिकी उपमिशन (एसएमएएफ) के तहत सहायता के लिए पूर्वापेक्षा में ट्रान्सिट विनियमन की छूट
- ◆ 8 राज्यों ने इस विनियमन में छूट प्रदान की है।

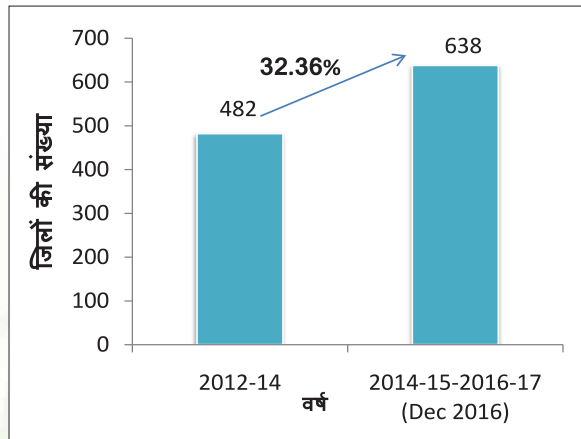
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)

कवर किए गए राज्यों की संख्या



वर्तमान शासन के दौरान एनएफएसएम के अंतर्गत राज्यों की संख्या 19 से बढ़ाकर 29 कर दी गई है।

कवर किए गए जिलों की संख्या



एनएफएसएम के अंतर्गत जिलों की संख्या 482 से बढ़ाकर 638 कर दी गई है जो लगभग 32.36 प्रतिशत की वृद्धि है।

- वर्तमान में एनएफएसएम के अंतर्गत 7 फसलों (चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज, गन्ने, जूट और कपास) को कवर किया जा रहा है, जबकि 2012-14 के दौरान केवल 3 फसलों को शामिल किया गया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)-दलहन

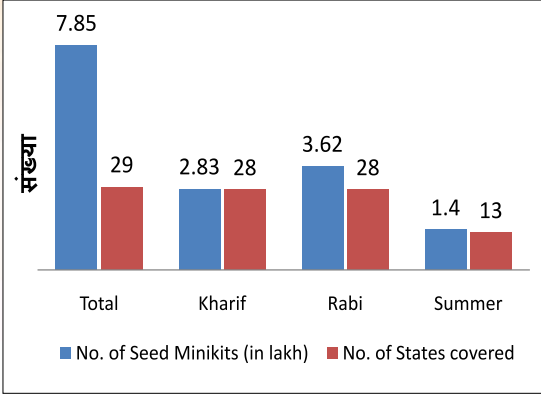


दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाये गए कदम

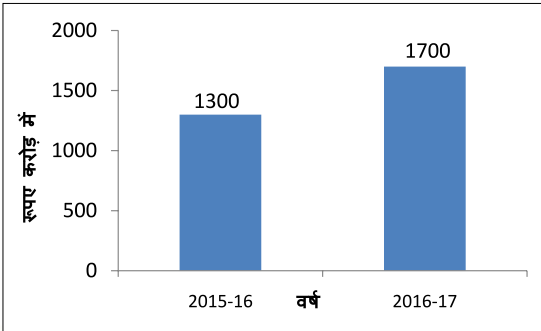
- ◆ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत 1700.00 करोड़ रु० की राशि में से दलहन के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान 1100.00 करोड़ रु० आवंटित किए गए जो कुल आवंटन की 60 प्रतिशत से भी अधिक राशि है।
- ◆ पूर्वी भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम के अंतर्गत चावल की परती भूमि वाले क्षेत्रों में दलहन की फसल को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- ◆ चावल की परती भूमि वाले क्षेत्रों को खेती के अंतर्गत लाने के लिए रबी 2016 से आरकेवीवाई के अंतर्गत "दलहन के लिए पूर्वी भारत में चावल की परती भूमि वाले क्षेत्रों को लक्षित करना" नामक विशेष स्कीम की शुरुआत की गई है।
- ◆ ग्रीष्म मूंग की फसल को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- ◆ धान खेतों के मेड़ों पर अरहर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- ◆ 2016-17 के 574 केवीके के माध्यम से 31000 क्लस्टर फ्रंट लाईन प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
- ◆ एसएयू/केवीके/आईसीएआर संस्थानों के 150 सीड हब स्वीकृत किए गए हैं।
- ◆ खरीफ 2016 से गुणवत्ता बीज उत्पादन के लिए एनएफएसएम के दलहन घटक का 15 प्रतिशत आवंटन निर्धारित किया गया।



राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)

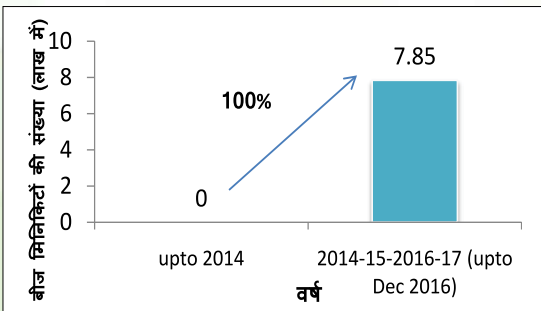


पहली बार 2016-17 के दौरान दलहन बीज मिनिकिट का वितरण पूरे देश भर में किये गये (दिसम्बर 2016 तक)।



केन्द्रीय हिस्से के अनुसार एनएफएसएम के लिए निधियों का आवंटन

चावल, गेहूँ, दलहन, मोटे अनाज, गन्ना, पटसन एवं कपास-फसलों के लिए एनएफएसएम के तहत बजट आवंटन में लगातार वृद्धि



एनएफएसएम के तहत दलहनों का बीज मिनिकिट वितरण लक्ष्य इस गतिविधि को खरीफ 2016 से एनएफएसएम के तहत शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पॉम मिशन

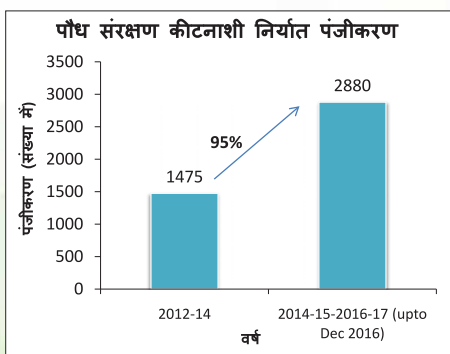
एनएमओओपी के सहायता पैटर्न में किए गए संशोधन

- ◆ प्रमाणीकृत तिलहन बीज वितरण के लिए बीज सब्सिडी को 100% से अधिक बढ़ाया गया था (संकर एवं तिल के लिए 1200 रू० से 2500 रू० प्रति क्विं० तथा 2500 रू० से 5000 रू० प्रति क्विं० तक)।
- ◆ पानी ले जाने वाले पाइप पर सब्सिडी को बढ़ाया गया जो एचडीपीई पाइप के लिए 25 रू० से बढ़कर 50 रू० प्रति मीटर, पीवीसी पाइप के लिए 35 रू० प्रति मीटर एवं इसके साथ खरीफ-2016 से 20 रू० प्रति मीटर की सब्सिडी के साथ एचडीपीई लेमिनेटस की वुवन ले प्लैट पाइप को शामिल करना।
- ◆ अगले तीन वर्षों में छह पूर्वी राज्यों के 10.00 लाख हैक्ट० चावल की परती भूमि को कवर करने के लिए रबी 2016 से आरकेवीवाई के अंतर्गत एक विशेष स्कीम "दलहन एवं तिलहन के लिए पूर्वी भारत में चावल की परती भूमि को लक्षित करना" की शुरुआत की गई है।
- ◆ वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न तिलहन फसलों के क्लस्टर प्रदर्शन एवं एफएलडी के लिए एसएयू से अधिक आईसीएआर के 423 केवीके शामिल हैं।
- ◆ वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न तिलहन फसलों के 16.0 लाख से भी अधिक बीज मिनीकिट्स वितरित किए गए थे।
- ◆ पूर्वोत्तर राज्यों में ऑयल पाम की खेती पर विशेष ध्यान दिया गया है। पिछले दो वर्षों के दौरान ऑयल पाम के अंतर्गत 25,000 हैक्ट० से अधिक क्षेत्र को कवर करते हुए मिजोरम सबसे आगे है एवं अक्टूबर, 2014 में मिजोरम में गोदरेज एग्रोवेट द्वारा एक ऑयल पाम प्रसंस्करण ईकाई शुरू की गई है।

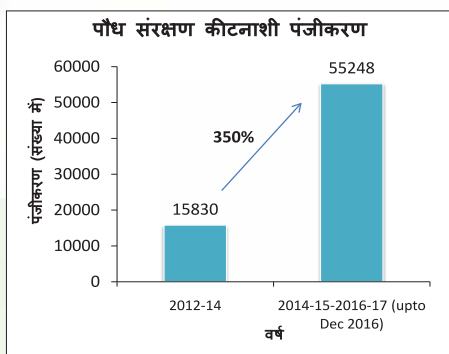


पौध संरक्षण

- ◆ पौध संरक्षण प्रभाग के ठोस प्रयासों के परिणाम स्वरूप वियतनाम ने भारतीय मूंगफली से प्रतिबंध हटा लिया है।
- ◆ 2014-15 से 2016-17 के दौरान 55,248 पंजीकरण प्रमाण पत्रों के अनुमोदन से कीटनाशी पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है। अब कोई बकाया नहीं रहा है।
- ◆ 2014-15 से 2016-17 के दौरान 2880 पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुमोदन से निर्यात के लिए कीटनाशी पंजीकरण में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- ◆ कृषि जिनसों के आयात के लिए परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
- ◆ कीटनाशियों के विनिर्माण लाइसेंस के नवीनीकरण की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
- ◆ 87 महत्वपूर्ण संशोधित फसलों के लिए आईपीएम पद्धति पैकज आनलाइन उपलब्ध कराया गया है।



2012-14 के दौरान पौध संरक्षण कीटनाशी निर्यात पंजीकरण में 95 प्रतिशत वृद्धि।



बेहतर निगरानी और प्रौद्योगिकी उपयोग से कीटनाशी पंजीकरण की संख्या में लगभग साढ़े तीन गुणा की वृद्धि हुई।

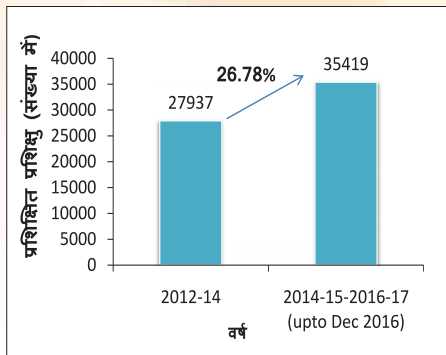
कृषि यंत्रीकरण



7-8 जुलाई, 2016 विज्ञान भवन, नई दिल्ली में कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के मशीनीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा कृषि यंत्रीकरण में नवाचार तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों- उद्योग- किसानों के मध्य सम्बन्धों के विकास पर दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

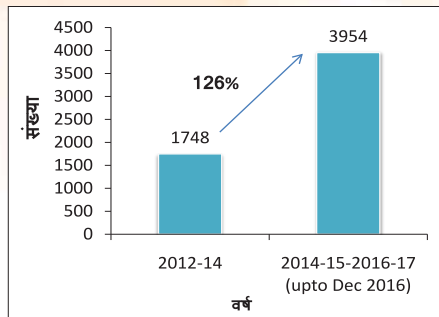
कृषि यंत्रीकरण

कृषि यंत्रीकरण



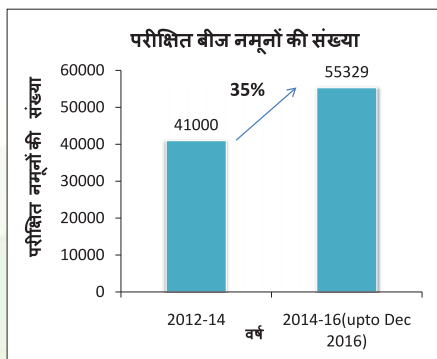
2012-14 के दौरान प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या की तुलना में 2014-16 के दौरान कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) के अंतर्गत एफएमटीआई और राज्य कृषि विभागों में अधिक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया। 2016-17 (दिसम्बर, 2016 तक) के दौरान एफएमटीआई में कुल 6868 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया।

एफएमटीआई और अभिनामित परीक्षण केन्द्रों में जांची गई कृषि मशीनरी



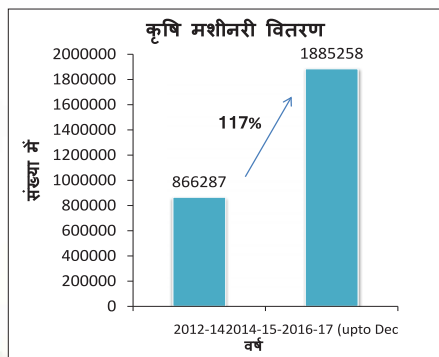
2012-14 के दौरान जांची गई मशीनों की संख्या की तुलना में 2014-16 के दौरान परीक्षण की गई मशीनरी की संख्या में 126 प्रतिशत की वृद्धि।

परीक्षित बीज नमूनों की संख्या



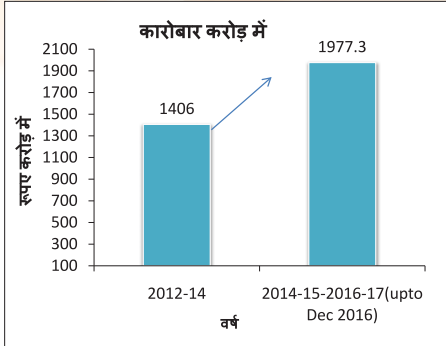
वर्ष 2012-14 के दौरान योजनाओं के लिए निधियों के आवंटन की तुलना में वर्ष 2014-16 में निधियों के आवंटन में 492 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

कृषि मशीनरी वितरण

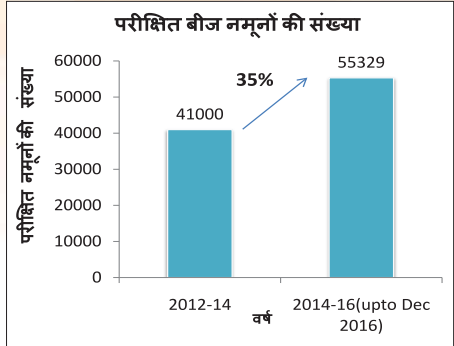


कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वर्ष 2012-14 के दौरान वितरित मशीनरी की तुलना में वर्ष 2014-16 के दौरान किसानों को सबसिडी पर वितरित मशीनरियों की संख्या में 117% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-17 (नवंबर, 2016 तक) के दौरान कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने अपने विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 1,885,258 कृषि मशीनरी वितरण को अनुमोदित किया है।

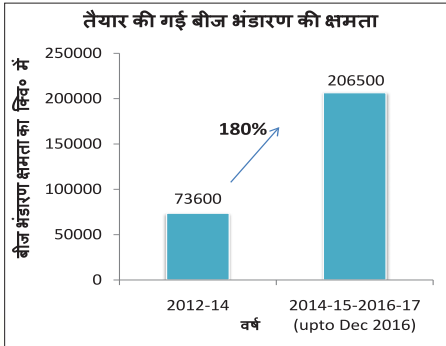
राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी)



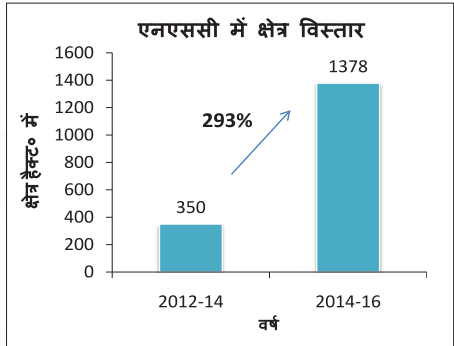
पिछले 2 वर्षों (2012-14) की तुलना में पिछले 2 (2014-16) वर्षों के दौरान कारोबार में 55% वृद्धि



पिछले 2 वर्षों (2012-14) की तुलना में वर्ष 2014-16 के दौरान 35% अधिक बीज नमूनों का परीक्षण किया गया है।



वर्ष 2012-14 की तुलना में 2014-16 के दौरान 180 प्रतिशत अधिक भण्डारण क्षमता को निर्मित किया गया।



2012-14 की तुलना में 2014-16 के दौरान खेतों के क्षेत्र विस्तार में 293 प्रतिशत की वृद्धि

पौध किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण के अंतर्गत किसानों को लाभ देने के लिए नई पहलें (2014 के बाद पीपीवी एवं एफआर अधिनियम)

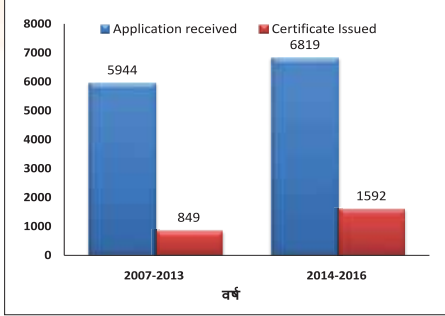
वर्ष 2014 के पश्चात पीपीवी एवं एफआर के तहत किसानों के लाभ के लिए नई पहल

- ♦ पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) में हाल ही में पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण की तीन नई शाखा कार्यालय स्थापित करने का अनुमोदन किया गया है जो उत्तरी पहाड़ी जोन के राज्यों को कवर करेगा, दूसरा पुणे (महाराष्ट्र) में जो मध्य और पश्चिमी जोन राज्यों को कवर करेगा और तीसरा शिवमोगा (कर्नाटक) दक्षिणी राज्यों के लिए है।
- ♦ "पौध जीनोम सेवियर" किसान पुरस्कार के लिए नगद पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दी गई है और वर्ष 2015 के दौरान किसानों की राशि प्रमाणीकरण शून्य से बढ़ाकर 1.00 लाख रुपये कर दी गई है।
- ♦ वर्ष 2015 के दौरान किस्मों के पंजीकरण के बाद किसान के लिए वार्षिक शुल्क 2000 रुपये प्रति वर्ष से घटाकर 10 रुपये मात्र कर दी गई है।

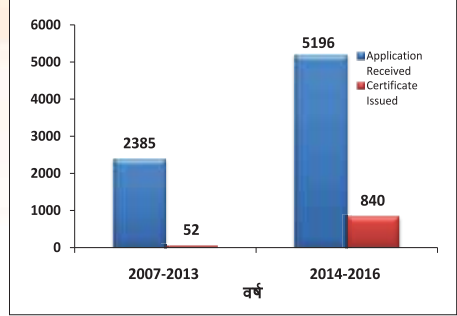


श्री राधा मोहन सिंह, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार, 24 अगस्त, 2016 को विशिष्ट लवण प्रतिरोधी गेहूँ के लिए खर्ची गांव राजस्थान के समुदाय के प्रतिनिधियों को एक मोमेंटों और प्रशस्ति पत्र के साथ 10 लाख रु. के पौध जीनोम सेवियर अवार्ड प्रदान करते हुए। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण और पंचायती राज्य मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला भी उपस्थित थे।

पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन एवं प्रदान किए गए आईपीआर प्रमाण-पत्र

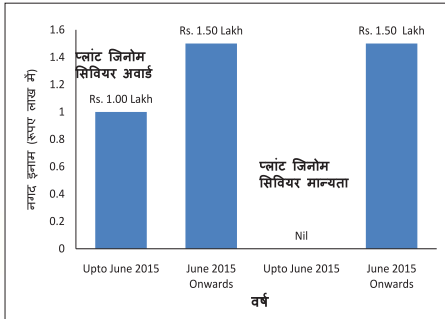


पीपीवी व एफआर अधिनियम के अंतर्गत किसानों से प्राप्त आवेदन एवं पंजीकृत किस्मों की संख्या

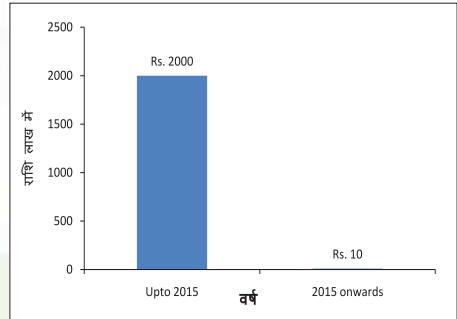


- वर्ष 2007 से पीपीवी व एफआर प्राधिकरण कुल 12763 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
- किसानों के हित के लिए सरकार द्वारा बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाने के कारण वर्ष 2013 से प्राप्त 47% आवेदनों की तुलना में वर्ष 2014 में 53% आवेदन प्राप्त हुए हैं।

पीपीवी व एफआर अधिनियम के अंतर्गत प्लांट जिनोम सेवियर अवार्ड के लिए नगद पुरस्कार में वृद्धि



पीपीवी एवं एफआर अधिनियम के अंतर्गत किसानों के वार्षिक शुल्क में कमी

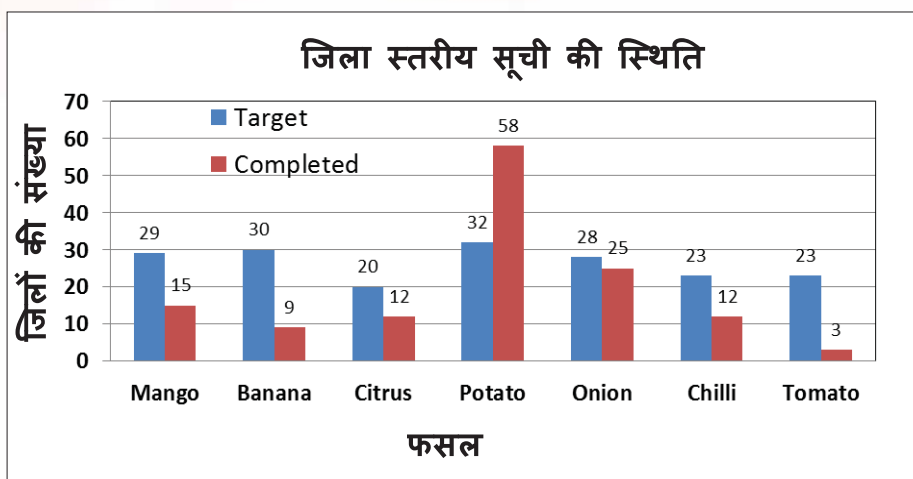


सरकार ने दिनांक 15 जून, 2015 के राजपत्र अधिसूचना सा० आ० 1598 (अ.सा.) के माध्यम से किसानों के वार्षिक शुल्क को 2000 रु० से घटाकर 10 रु० कर दी।

सरकार ने दिनांक 15 जून, 2015 की राजपत्र अधिसूचना 495 (अ.सा.) के माध्यम से यह निर्णय लिया कि नगद अवार्ड की राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया। तदनुसार केन्द्रीय सरकार ने "प्लांट जिनोम सेवियर" के लिए नगद ईनाम की राशि को 1.00 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रु० तथा किसान के पुरस्कार की राशि को शून्य से बढ़ाकर 1.00 लाख रु० कर दी।

महलानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी) चमन (समन्वित बागवानी आकलन एवं जियो इंफोरमेटिक्स का प्रयोग करते हुए प्रबंधन)

- ◆ सितम्बर, 2014 में शुरू।
- ◆ रिमोट सेंसिंग और फसल क्षेत्र में जीआईएस का उपयोग और 135 जिलों (लक्ष्य 180) में 7 बागवानी फसलों का उत्पादन आकलन।
- ◆ साइट अनुकूलता, बागान पुनरूद्धार, फसलोंपरांत अवसंरचना, जलीय बागवानी में बागवानी विकास नियोजन हेतु रिमोट सेसिंग का उपयोग।



महलानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी) स्पेस प्रौद्योगिकी और जिओ इंफोरमेटिक्स का प्रयोग करके किसान फसल बीमा

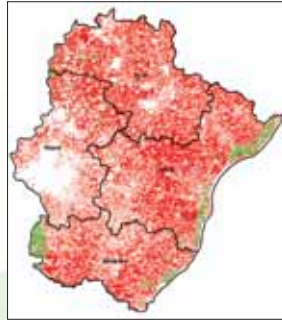
- ◆ अक्टूबर 2015 में शुरू ।
- ◆ उन्नत फसल आकलन के लिए हाई रिजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग का उपयोग ।
- ◆ पीएमएफबीवाई (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) के तहत 7 चावल जिलों और 4 कपास जिलों हेतु सीसीई साइट चयन ।
- ◆ सीसीई डाटा की गुणवत्ताप्रद जांच के लिए प्रोटोकॉल तैयार करना ।
- ◆ गुजरात हेतु रिमोट सेंसिंग डाटा का उपयोग करके क्षेत्र विषमता विश्लेषण ।

चावल की परती भूमि क्षेत्र में फसल गहनीकरण

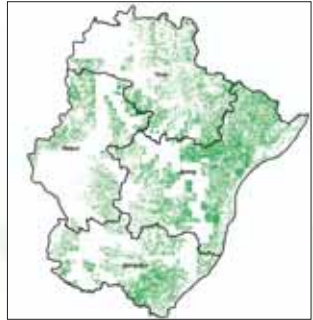
- ◆ सितम्बर 2016 में शुरू ।
- ◆ उद्देश्य 6 राज्यों में रबी फसलों हेतु फसल गहनीकरण के लिए चावल परती भूमि क्षेत्र आकलन और विशेषताएं ।
- ◆ छत्तीसगढ़ और ओडिसा राज्यों के प्रत्येक में दो जिलों हेतु विश्लेषण किए गए ।
- ◆ रबी मौसम फसलन के लिए अनुकूल क्षेत्र हेतु ब्लॉक लेबल मानचित्र और सांख्यिकी तैयार की गईं ।



खरीफ चावल



खरीफ चावल – रबी परती भूमि
खरीफ चावल–रबी फसल



रबी फसलन हेतु अनुकूल क्षेत्र

छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में रबी मौसम फसलन हेतु अनुकूल चावल परती भूमि क्षेत्र ।

जलवायु परिवर्तन चुनौतियां का समाधान करना

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:

- ◆ कृषि पर जलवायु परिवर्तन पर होने वाले प्रभाव से आहार, आजीविका व समग्र अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- ◆ छोटे व सीमांत किसान चरवाहों व मछली उद्योग पर भी प्रभाव पड़ता है।
- ◆ देश के कुल उत्सर्जन में कृषि का योगदान 18% है। एंटीक फरमेन्टेशन, धान की खेती, उर्वरक व फसल अवशेष जलाने से जीएचजी में वृद्धि होती है।

जलवायु परिवर्तन जोखिम		सहायक कारक	संस्तुत प्रणालियां
प्रत्यक्ष प्रभाव	अप्रत्यक्ष प्रभाव	<input type="checkbox"/> जलमग्न चावल की खेती	<input type="checkbox"/> कुशल जल उपयोग/जल संचयन
❖ उत्पादकता	❖ मृदा उर्वरता	<input type="checkbox"/> उर्वरकों का अवैज्ञानिक उपयोग	<input type="checkbox"/> जलवायु अनुकूल फसल किस्में
❖ उपज की गुणवत्ता	❖ पशुधन व मात्स्यिकी	<input type="checkbox"/> पशुओं से होने वाला उत्सर्जन	<input type="checkbox"/> फसल विविधीकरण व फसल संरक्षण
	❖ मृदा व जल संसाधन	<input type="checkbox"/> मृदा में कम जैविक पदार्थ	<input type="checkbox"/> जैविक कृषि
	❖ फसल स्वास्थ्य		<input type="checkbox"/> समेकित पोषक तत्व प्रबंधन आधारित मृदा स्वास्थ्यक इंडेक्स
			<input type="checkbox"/> पशु आहार प्रबंधन
			<input type="checkbox"/> कृषि वानिकी

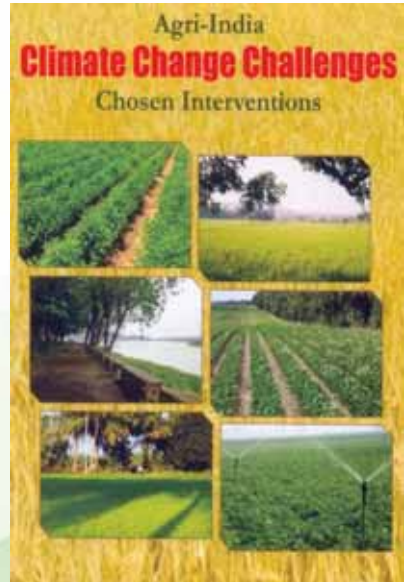
केन्द्र सरकार की स्कीमें व नीतिगत पहल	
➤ मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम	➤ राष्ट्रीय व जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम
➤ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	➤ राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन
➤ परम्परागत कृषि विकास योजना	➤ राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति
➤ कृषि वानिकी उप-मिशन	➤ राष्ट्रीय फसल अवशेष प्रबंधन नीति
➤ समेकित कृषि विकास मिशन	➤ राशन संतुलन कार्यक्रम
➤ राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन	

जलवायु परिवर्तन एवं कृषि

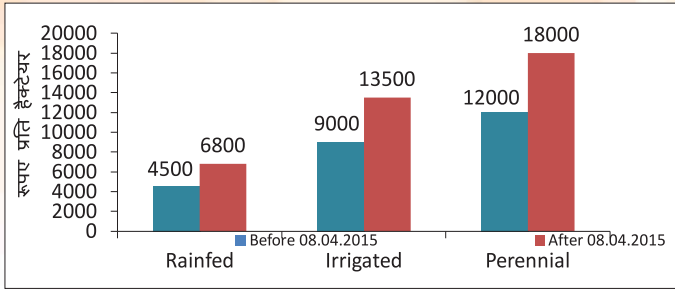
कार्रवाई एवं प्रगति:

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के प्रमुख कार्यक्रम:

- ♦ जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) के अंतर्गत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिज-21 (सीओपी-21) में प्रतिनिधित्व कृषि क्षेत्र से संबंधित पेरिस समझौता पर चर्चा करना।
- ♦ जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) के अंतर्गत मोरक्को में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिज-22 (सीओपी-22) में प्रतिनिधित्व।
- ♦ कृषि क्षेत्र से संबंधित पेरिस समझौता के मुद्दों का समर्थन।
- ♦ राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन परिषद (पीएमसीसीसी) की जलवायु परिवर्तन पर कार्यकारी समिति की पांच समीक्षा बैठकों में भाग लेना।
- ♦ सात वर्षीय कार्यनीति सहित 15 वर्ष अर्थात् 2030 तक के लिए विजन डॉक्यूमेंट का मसौदा तथा सतत कृषि लक्ष्य (एसडीजी) पर तीन वर्षीय कार्य योजना को नीति आयोग का सौंपा गया है।
- ♦ जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्यक्रमों पर पुस्तिका प्रकाशित करना।
- ♦ पिछले तीन वर्षों के दौरान जैविक कृषि के अंतर्गत 18.36 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल, सुव्यवस्थित सिंचाई के अंतर्गत 20.07 लाख हैक्टेयर, एसआरआई/ डीएसआर चावल की खेती के अंतर्गत 6.36 लाख हैक्टेयर व 6.73 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्रफल को खेती योग्य भूमि में रोपण के अंतर्गत लाया गया है।
- ♦ अधिक कार्बन डाइऑक्साइड निर्धारण क्षमता वाले 41 नए जीनोटाइप को चिह्नित किया गया है।
- ♦ 42 नई जलवायु अनुकूल किस्मों जारी की गई है।
- ♦ राशन संतुलन कार्यक्रम के अंतर्गत 9.68 लाख दुधारू पशुओं को शामिल किया गया।

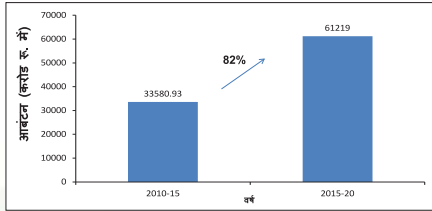


सूखा प्रबंधन-आपदा राहत उपायों में परिवर्तन

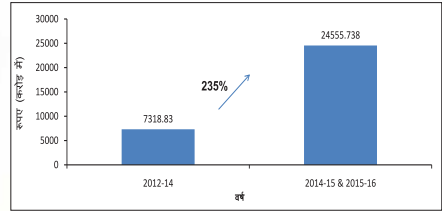


- ◆ सभी श्रेणी की सहायता मापदंड 1.5 गुना बढ़ाए गए हैं।
- ◆ फसल हानि के कारण सहायता के लिए को 50 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत कर दिया गया।
- ◆ सभी मामलों में सहायता की ग्राह्यता को 1 हेक्टेयर से बढ़ाकर 2 हेक्टेयर कर दिया गया।
- ◆ मृत्यु की स्थिति से किसानों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 1.5 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया।

राज्य आपदा अनुक्रिया कोष के अंतर्गत राज्यों को प्राकृतिक आपदा निधियों का आबंटन



प्राकृति आपदा और एनडीआरएफ के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्यों को अनुमोदित केन्द्रीय सहायता



- ◆ एसडीआरएफ के अंतर्गत आवंटन को लगभग दुगुना कर दिया गया है।
- ◆ इस निधि से आपदा के साथ निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने हेतु राज्य सरकार की सहायता
- ◆ सूखा तथा ओलावृष्टि के लिए एनडीआरएफ के अधीन सहायता में महत्वपूर्ण वृद्धि
- ◆ पूर्व के 4 वर्षों में 12,516 करोड़ रु. के अनुमोदन की तुलना में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में 24555.74 करोड़ रु. अनुमोदित किया गया जो लगभग दुगुना है।
- ◆ प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत सहायता के लिए पहली बार 50 करोड़ रु आवंटन के साथ यूटी-डीआरएफ निधि बनाई गयी।

किसान सुविधा मोबाइल एप की शुरुआत



19 मार्च, 2016 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किसान सुविधा एप की शुरुआत की गई थी ताकि महत्वपूर्ण मापदंडों अर्थात् मौसम, पौध संरक्षण, आदान डीलरों, कृषि-परामर्शदात्री एवं मंडी मूल्य आदि पर किसानों के लिए सूचना प्रदान की जा सके।

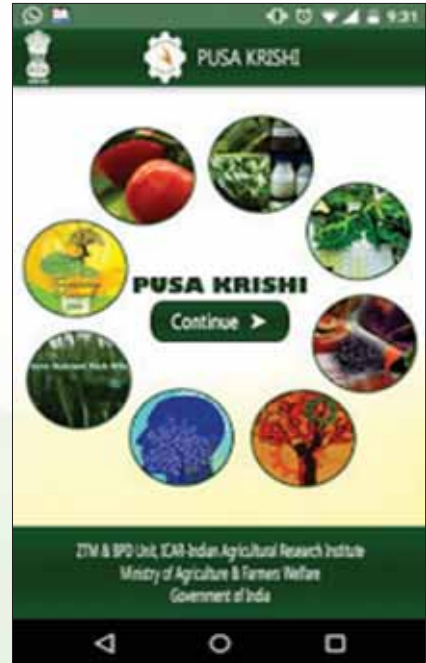
सूचना प्रौद्योगिकी

किसानों के लिए मोबाइल एप शुरू करना



संवेदनशील मानकों यथा जलवायु, पौध संरक्षण, आदान डीलरों, कृषि परामर्शों और मंडी मूल्य आदि पर किसानों को सूचना प्रदान करने के लिए 19 मार्च, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किसान सुविधा एप शुरू की गयी थी।

हमारे प्रधानमंत्री के प्रयोगशाला से खेत तक के सपने को साकार करने के लिए माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री द्वारा पूसा मोबाइल एप किसानों की सहायता के लिए शुरू की गई। आईएआरआई द्वारा इस विकसित प्रौद्योगिकी से किसान सूचना प्राप्त कर सकते हैं।



सूचना प्रौद्योगिकी



ऋणी किसानों के मामलों में क्षेत्र कवरेज राशि और ऋण राशि पर आधारित अधिसूचित फसलों के लिए बीमा प्रीमियम के परिगणन के लिए फसल बीमा मोबाइल एप शुरू किया गया है। इससे हम सामान्य, बीमित राशि, विस्तृत, प्रीमियम ब्यौरा और किसी भी अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी अधिसूचित फसल की राज्य सहायता सूचना के बारे में ब्यौरा प्राप्त कर सकते हैं।

मोबाइल जीपीएस का उपयोग करते हुए डिवाइस स्थान के 50 किमी. के क्षेत्र के अधीन मंडियों से जिसों की मंडी मूल्य प्राप्त करने में कृषि मंडी एप का उपयोग कर सकते हैं।

किसी भी मंडी और किसी भी फसल का मूल्य प्राप्त करने के लिए अन्य विकल्प भी है यदि कोई व्यक्ति जीपीएस स्थान का उपयोग नहीं करना चाहता।



सूचना प्रौद्योगिकी

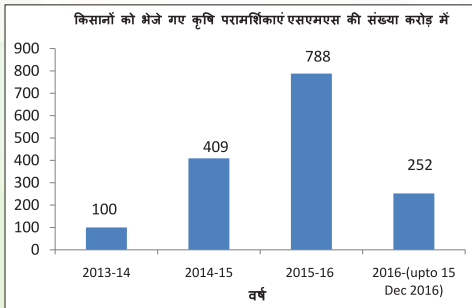


सीसीई कृषि - मोबाइल एप

- ◆ खेत में संचालित कटाई पश्चात प्रयोग की सूचना को डिजिटल कराने के लिए सीसीई कृषि मोबाइल एप विकसित की है।
- ◆ जीपीएस के माध्यम से खेत का स्थान स्वतः ही ग्रहण कर लेता है।
- ◆ एप के माध्यम से लिए गए फोटोग्राफ एवं डाटा को वेब सर्वर त्वरित ट्रांसफर करता है।
- ◆ दावा निपटान समय को कम करता है और पारदर्शिता का स्तर प्राप्त किया है।

फसल बीमा पोर्टल

- ◆ किसानों राज्यों, बीमा कंपनियों एवं बैंकों सहित सभी स्टैकहोल्डरों के लिए एक ही पोर्टल
- ◆ दोनों बीमा स्कीमें यथा पीएमएफबीवाई और डब्ल्यूबीसीआईएस कवर है।
- ◆ मोबाइल एप के माध्यम से और वेब पर प्रीमियम अंतिम तारीख एवं किसानों को उनके फसल एवं स्थान के लिए कंपनी संपर्कों की सूचना
- ◆ बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर एवं अधिसूचित डाटाबेस का सृजन
- ◆ ऋण/बीमा हेतु किसानों के आवेदन और बैंकों के साथ इनका समेकन।



सामाजिक मीडिया कार्यकलाप

Facebook: www.facebook.com/agrigoi

Likes: 5619

Twitter @agrigoi

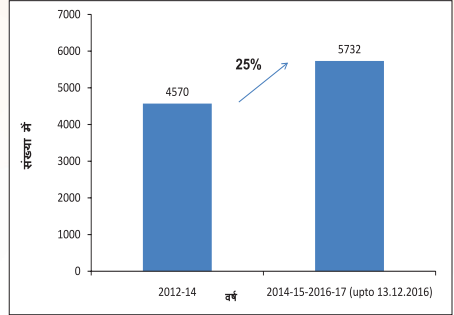
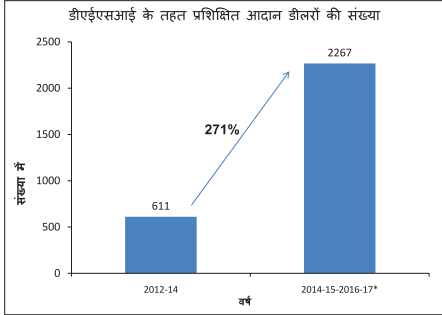
Followers: 33000

Youtube Channels: कृषि भारत और कृषि दर्शन

Videos: 1200

कृषि विस्तार

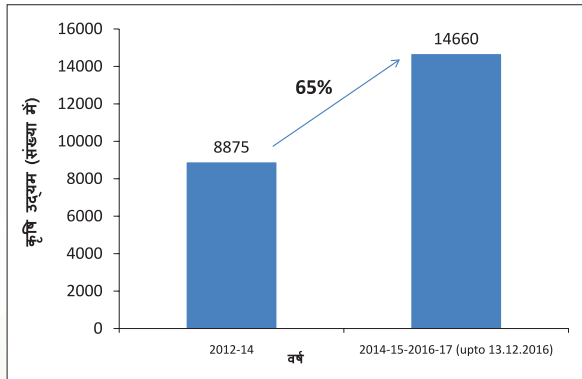
कृषि क्लीनिक एवं कृषि बिजनेस केन्द्र (एसीएबीसी) के अंतर्गत स्थापित कृषि-उद्यम



वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान आदान डीलरों के प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है ।

वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान एसीएबीसी योजना के तहत स्थापित कृषि उपक्रम में महत्वपूर्ण वृद्धि ।

कृषि-क्लीनिक एवं कृषि बिजनेस केन्द्रों के अंतर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थी



वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान एसीएबीसी योजना के तहत प्रशिक्षित अभ्यर्थी में महत्वपूर्ण वृद्धि ।

कृषि विस्तार

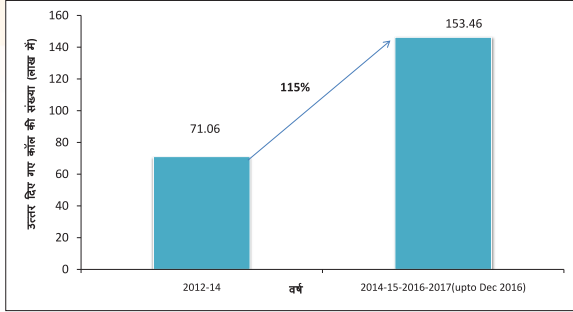
कृषि में कौशल विकास:

- ◆ 2016–17 के दौरान कौशल विकास के लिए एमएसडीई के साथ 100 केविके और 8 प्रशिक्षण संस्थानों को प्रत्यायित किया गया।
- ◆ 2016–17 के दौरान 216 कौशल प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए 3.52 करोड़ रु. की संस्तुति।
- ◆ कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण के लिए एएससीआई द्वारा 132 क्यूपीएस विकसित।
- ◆ देश भर में एएससीआई के साथ संबद्ध 333 प्रशिक्षण सहयोगी।
- ◆ कौशल प्रशिक्षणों की पहुंच बढ़ाने के लिए एमएसडीई, एएससीआई और अन्य पणधारियों के साथ संपर्कों को मजबूत किया गया।
- ◆ अगले चरण (2017–18) में 100 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्रों को शामिल किया जाना है।



कृषि विस्तार

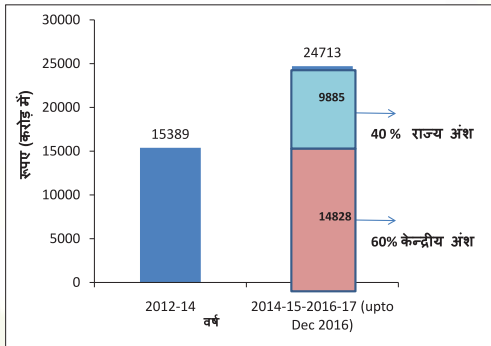
किसान काल केन्द्रों पर दिए गए उत्तर (संख्या लाख में) 1800-180-1551



- वर्ष 2012-14 के दौरान 71.06 लाख फोन के उत्तर दिए गए और वर्ष 2014-17 के दौरान 31 अक्टूबर 2016 तक दिए गए उत्तरों की संख्या 153.46 लाख है।
- वर्ष 2013-14 तक प्रतिवर्ष दिए गए उत्तर का औसत 35.53 लाख है जहां वर्ष 2015-16 में दिए गए उत्तरों की संख्या 53.79 लाख प्रति वर्ष है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

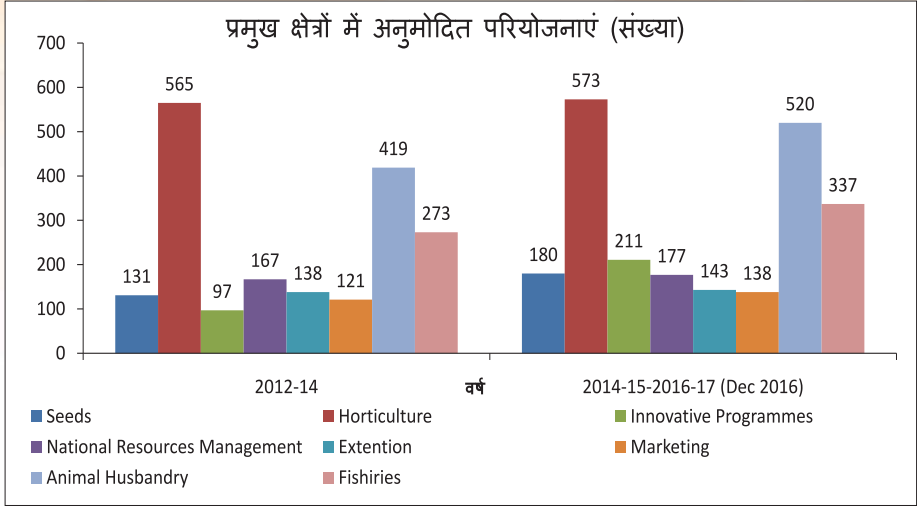
आरकेवीवाई के अंतर्गत निर्मुक्त बजट



वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 (दिसम्बर 2016 तक) के दौरान हेतु 60% केन्द्रीय अंश रु. 14828 करोड़ और 40 प्रतिशत राज्य अंश रु. 9885 करोड़।

- सरकार ने कृषि एवं समर्थी क्षेत्र में निवेश और उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्यों को अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए वर्ष 2014-15 में पुनर्गठित आरकेवीवाई स्कीम शुरू की है।
- कृषि अवसंरचना निर्माण के लिए आरकेवीवाई परियोजना का 35 प्रतिशत निर्धारित है।
- कृषि एवं समर्थी क्षेत्र में अवसंरचना परियोजना को और मजबूत करने के लिए सरकारी एजेंसियां भी आरकेवीवाई स्कीम से 100 प्रतिशत वित्तपोषण के साथ संपदा/अवसंरचना के निर्माण हेतु परियोजना कार्यान्वयन की अनुमति दी गई है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)



- ◆ पुनर्गठित आर के वी वाई ने फ्लैक्सी फंड के रूप में 10 प्रतिशत प्रावधान रखने के लिए राज्यों को अनुमति दी है जो सूखा प्रशमन उद्देश्य के लिए भी उपयोग की जा सकती है।
- ◆ पुनर्गठित आरकेवीवाई में राष्ट्रीय आयात के विशेष स्कीमों के लिए वार्षिक परिव्यय का 20 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग



- ◆ पिछले 2.5 वर्षों के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 5 देशों—अर्मेनिया, मैडागास्कर, लिथुआनिया, जापान एवं किर्गिस्तान के साथ कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा ताइपे के भारत—ताइपे संघ एवं भारत के ताइपे आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र ने भी इसी प्रकार के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इससे विभिन्न देशों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की कुल संख्या 58 है।
- ◆ कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने 23 सितंबर, 2016 को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 6वीं बैठक को सफलतापूर्वक आयोजित किया। हमारे आगे के कार्यक्रमों एवं निरंतर सहयोग से संबंधित संयुक्त घोषणा को सर्वसम्मति से अपनाया गया।
- ◆ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने फिक्की के सहयोग से 10—11 फरवरी, 2016 को नई दिल्ली में भारत अफ्रीका—कृषि व्यवसाय फोरम को सफलतापूर्वक आयोजित किया जिसमें विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी अधिकारियों एवं कंपनी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- ◆ 18.08.2015 को यूएन—विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा 07.11.2016 को ग्लोबल क्रॉप डाइवर्सिटी ट्रस्ट (जीसीडीटी), बॉन, जर्मनी के साथ भारत सरकार ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।
- ◆ 13 व 15 जुलाई, 2015 को तजिकिस्तान एवं कीर्गिस्तान के दशांबे एवं विशकेक में कृषि कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था जबकि 26 अप्रैल, 2016 को नई दिल्ली में एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें यूएसडीए के विशेषज्ञों एवं अधिकारियों ने भाग लिया।



स्वच्छता पखवाड़ा (अक्टूबर 2016)



एक कदम स्वच्छता की ओर

- ◆ पखवाड़े के दौरान स्वच्छ भारत अभियान में 271 मण्डियों को कवर किया गया था और संबद्ध कार्यालयों के साथ साथ कृषि भवन मुख्यालय में सफाई अभियान आयोजित किए गए।
- ◆ ई-एनएएम योजना के तहत अपशिष्ट प्रबंधन योजना की स्थापना के लिए प्रत्येक मण्डी के लिए 10 लाख रु. प्रति मण्डी के प्रावधान का निर्णय किया गया।
- ◆ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की उपयोजना के रूप में कृषि योजना में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तैयार करने का निर्णय लिया गया था। जिसके लिए राज्यों को निर्मुक्ति के लिए उस उप-योजना के तहत आरकेवीवाई के आवंटन का 1 प्रतिशत आवंटित किया जाएगा।
- ◆ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ 27.10.2016 को एक वीडियो कांफ्रेंस आयोजित की गई थी और उन्हें "स्वच्छ पखवाड़ा कार्यकलापों" के बारे में संक्षेप में बताया गया था। उन्हें कंपोस्ट फार्म अपशिष्ट तैयार करने के लिए उनकी विद्यमान योजनाओं में पर्याप्त प्रावधान का अनुरोध किया गया।

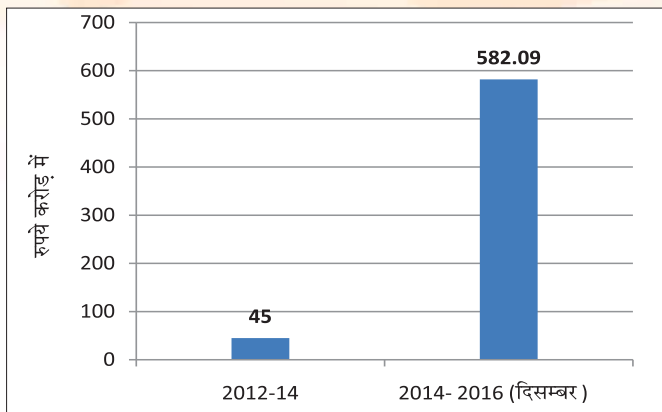


**पशुपालन, डेयरी
और
मत्स्यपालन विभाग**



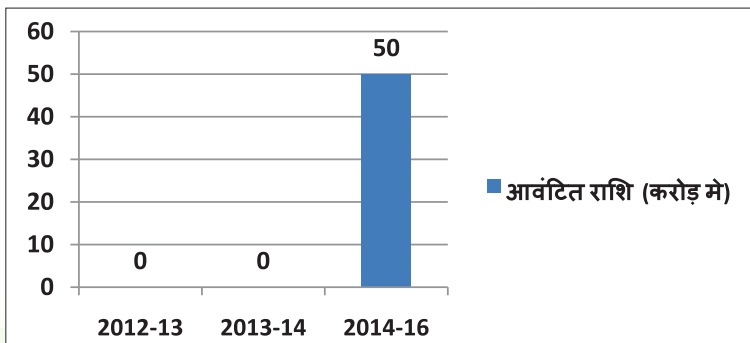
डेयरी विकास

देशी नस्लों के विकास और संवर्धन के लिए अनुमोदित निधि



देशी नस्लों के विकास और संवर्धन पर वैज्ञानिक और संपूर्ण रूप से बजट आवंटन में विविध बढ़ोत्तरी के साथ ध्यान केंद्रित करना। पिछले 2.5 वर्षों के दौरान 2012-13 और 2013-14 की तुलना में 13 गुना बजट आवंटन

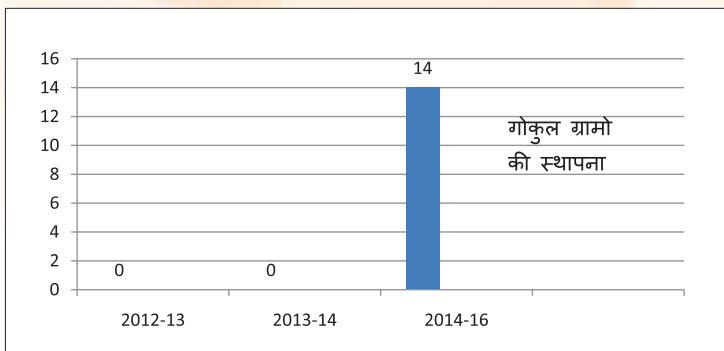
राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र



देश में दो नए नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर (एक उत्तर भारत- मध्य प्रदेश और एक दक्षिण भारत- आंध्र प्रदेश में) स्थापित किए जा रहे हैं जिसके लिए रु० 50 करोड़ जारी की जा चुकी है (25 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश तथा 25 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश को)।

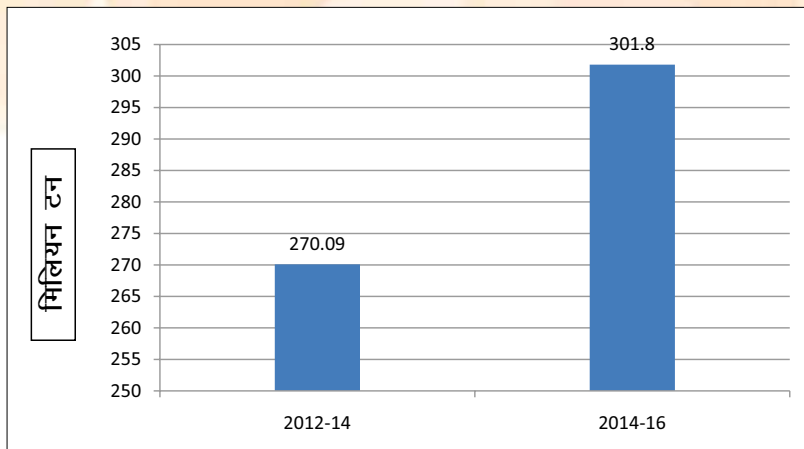
राष्ट्रीय गोकुल मिशन

देश में पहली बार राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी नस्लों के विकास और संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करना



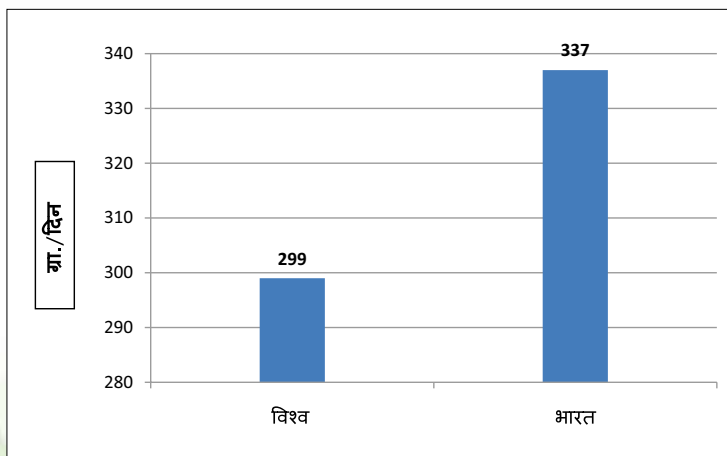
- ◆ पहली बार देशी नस्लों के संवर्धन और संरक्षण हेतु 14 गोकुल ग्रामों की स्थापना।
- ◆ देशी नस्लों के 35 सांड माता फार्मों के सुदृढीकरण हेतु राशि स्वीकृत तथा पहली किश्त जारी की गयी।
- ◆ देशी नस्लों के 3629 सांड प्राकृतिक गर्भाधान के लिए प्रतिष्ठापित किए गए। देशी नस्लों के 81 सांड वीर्य स्टेशनों पर वीर्य उत्पादन हेतु प्रतिष्ठापित किए गए
- ◆ ए2 दूध के विपणन की अलग से व्यवस्था करने के लिए ओड़ीशा एवं कर्नाटक राज्य को 2-2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गयी।
- ◆ क्षेत्र प्रदर्शन रिकॉर्डिंग कार्यक्रम (FPRP) की स्थापना के लिए फंड की मंजूरी दे दी गई है और पहली किस्त 1,50,000 स्वदेशी जानवरों के लिए जारी कर दिया गया है।
- ◆ देशी नस्लों के 81 सांड वीर्य स्टेशनों पर वीर्य उत्पादन हेतु प्रतिष्ठापित किए गए। प्राकृतिक सेवा के लिए स्वदेशी नस्लों का सांड उत्पादन कार्यक्रम मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात की ओर से शुरू किया गया है।

1. दूध का रिकार्ड उत्पादन (मि. टन)



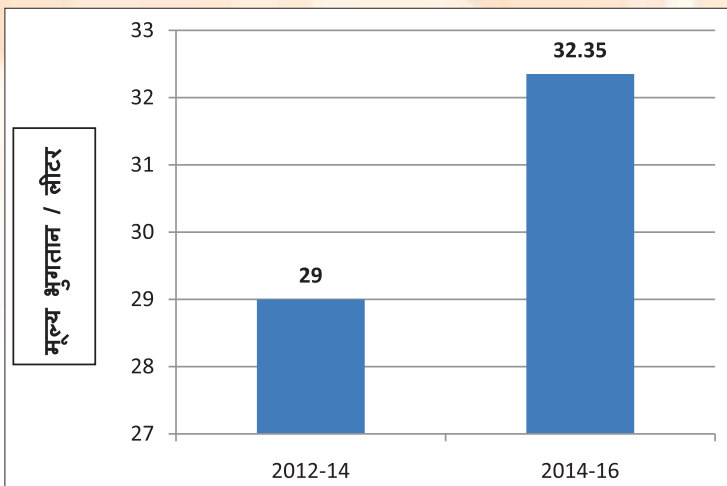
वर्ष (2012-14) की अपेक्षा वर्ष (2014-16) में वृद्धि दर 11.7% रही। पहली बार वर्ष 2015-16 के दौरान दुग्ध उत्पादन में वार्षिक वृद्धि 6.3% की हुई है

2. दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्रा./दिन)



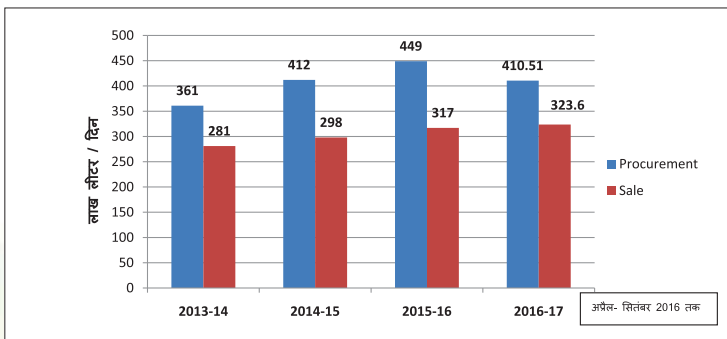
दूध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है
भारत विश्व दुग्ध उत्पादन में 19% का योगदान देता है

3. किसानों को भुगतान किए गए औसत मूल्य में बढ़ोत्तरी



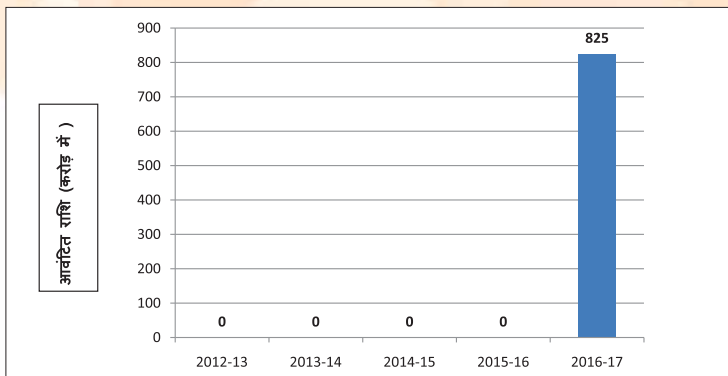
डेयरी किसानों की आय में पिछले 2.5 वर्षों के दौरान 11.5% की औसत वृद्धि दर्ज की गई है।

4. दुग्ध प्राप्ति/बिक्री में प्रभावशाली वृद्धि



सहकारिता क्षमता: उपभोक्ता मूल्य का 75% किसानों को जाता है।

नई योजनाएँ



बोवाइन उत्पादकता राष्ट्रीय मिशन योजना के लिए 825 करोड़ रु. का अनुमोदन तीन वर्षों 2016-17 से 2018-19 निम्नलिखित घटकों के लिए किया गया है:

- ♦ **पशुधन संजीवनी:** यह एक पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम है इसके भाग हैं: 1) पशु स्वास्थ्य कार्ड (नकुल स्वास्थ्य पत्र), 2) यूनिक पहचान संख्या और 3) राष्ट्रीय डाटाबेस।
- ♦ **उन्नत प्रजनन प्रौद्योगिकी:** असिसटेड प्रजनन तकनीक सहित: इस योजना का उद्देश्य रोगमुक्त मादा बोवाईनों की उपलब्धता को बढ़ाना एवं उन्नत बनाना है।
- ♦ **ई-पशुधन हाट का निर्माण:** देशी बोवाईन नस्लों के प्रजनकों और किसानों को जोड़ने एवं बोवाईन जर्मप्लांजम के लिए ई-मार्केट की स्थापना।
- ♦ **राष्ट्रीय जीनोमिक केंद्र:** तीव्र आनुवांशिक उन्नयन के जरिए देशी नस्लों के दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जीनोमिक केंद्र की स्थापना।

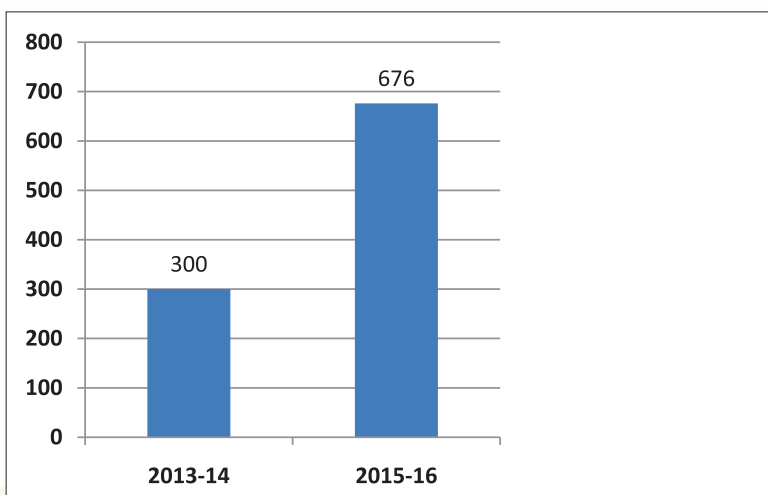
देश में पहली बार ई पशुधन हाट पोर्टल

- ♦ देश में पहली बार राष्ट्रीय बोवाइन उत्पादकता मिशन के अंतर्गत ई पशुधन हाट पोर्टल स्थापित किया गया है। यह पोर्टल देशी नस्लों के लिए प्रजनकों और किसानों को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- ♦ वर्तमान में देश में उच्च गुणवत्ता एवं रोग मुक्त वाले जर्मप्लाज्म जैसे वीर्य, भ्रूण, बछड़े, बछड़ी और वयस्क पशुओं का कोई भी प्रामाणिक बाजार नहीं है। अच्छी नस्ल के पशुओं की खरीद के लिए किसानों को बिचौलियों पर निर्भर होना पड़ता है।
- ♦ पशुओं की नस्ल वार सूचना भी किसानों को उपलब्ध नहीं होती जो कि देशी नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- ◆ इस पोर्टल द्वारा किसानों को देशी नस्लों की नस्ल वार सूचना प्राप्त होगी। इससे किसान एवं प्रजनक देशी नस्ल की गाय एवं भैंसों को खरीद एवं बेच सकेंगे। देश में उपलब्ध जर्मप्लाज्म की सारी सूचना पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है। जिससे किसान इसका तुरंत लाभ उठा सके। इस तरह का पोर्टल विकसित डेयरी देशों में भी उपलब्ध नहीं है।
- ◆ इस पोर्टल के द्वारा देशी नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन को एक नई दिशा मिलेगी। क्योंकि वर्तमान में किसानों के पास कोई नस्ल वार सूचना उपलब्ध नहीं है।
- ◆ पोर्टल के माध्यम से जानवरों की खरीद और बिक्री में बिचौलियों की कोई भागीदारी नहीं होगी। जर्मप्लाज्म के सभी रूपों में बिक्री और खरीद के लिए इस तरह का पोर्टल विकसित डेयरी देशों में भी उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन

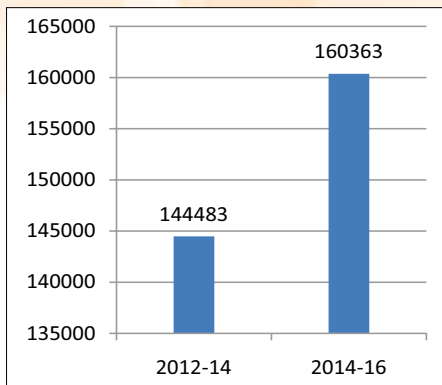
पहली बार सभी जिलों को राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया



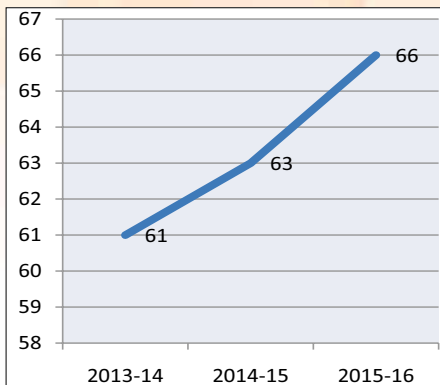
पशुधन बीमा का विस्तार और कवरेज को 300 जिलों से बढ़ाकर सभी जिलों 676 में कर दिया गया है तथा इसे 2 दुधारु पशुओं से बढ़ाकर 5 दुधारु पशुओं/अन्य पशु अथवा 50 छोटे पशुओं तक कर दिया गया है।

अंडा उत्पादन एवं उपलब्धता

अंडा उत्पादन (मिलियन में)



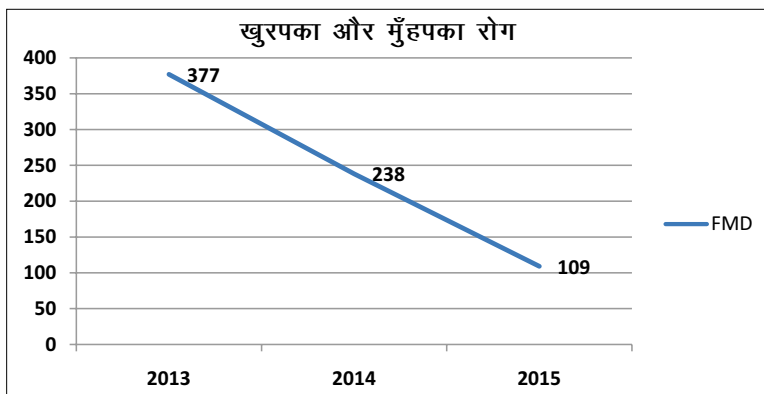
अंडा प्रति व्यक्ति (सं./वार्षिक)



वर्ष (2012-14) की अपेक्षा वर्ष (2014-16) में वृद्धि दर 10.99% रही। वर्ष 2015-16 के दौरान अंडा उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 5% है।

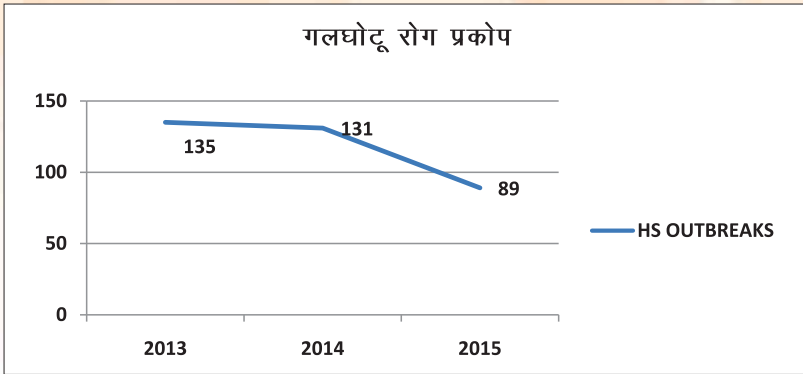
प्रति व्यक्ति उपलब्धता प्रतिवर्ष 66 अंडे तक पहुँच गई है।

पशु स्वास्थ्य



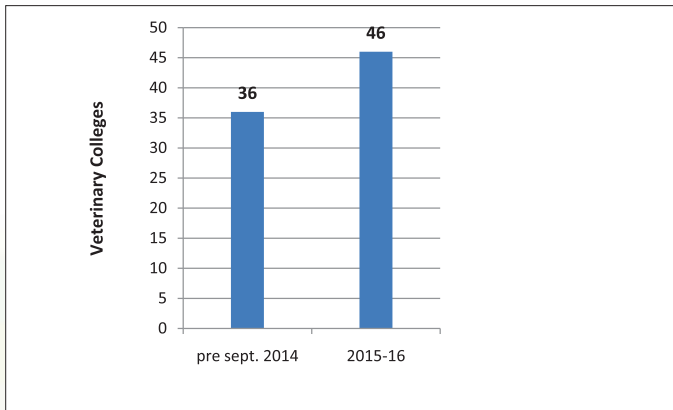
वर्ष 2015 के दौरान वर्ष 2013 की तुलना में एफएमडी प्रकोपों के क्षेत्र में भारी कमी दर्ज की गई। वर्ष 2013 में 377 रिकार्ड की गई जबकि वर्ष 2015 के दौरान घटकर यह प्रकोप केवल 109 थे जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 2016 (जनवरी से जून तक) के दौरान केवल 106 प्रकोप सूचित किया गया है। एफएमडी नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के आधार पर, तीन जोन को OIE दिशा निर्देशों के अनुसार टीकाकरण के साथ एफएमडी मुक्त क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया है।

गलघोटू प्रकोपों में भारी कमी दर्ज की गई



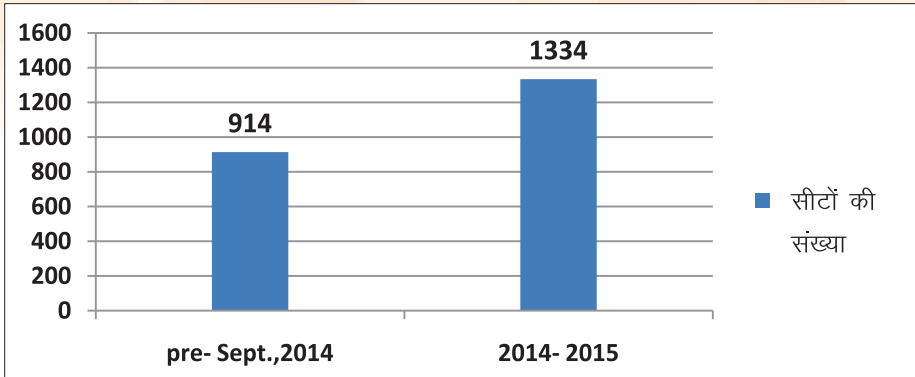
वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 के दौरान गलघोटू रोग के प्रकोपों में भारी कमी आई है तथा वर्ष 2015 के दौरान यह घटकर 89 हो गये। 2016 (जनवरी से जून तक) के दौरान केवल 40 प्रकोप सूचित किया गया है।

पशु चिकित्सा महाविद्यालय की संख्या में वृद्धि



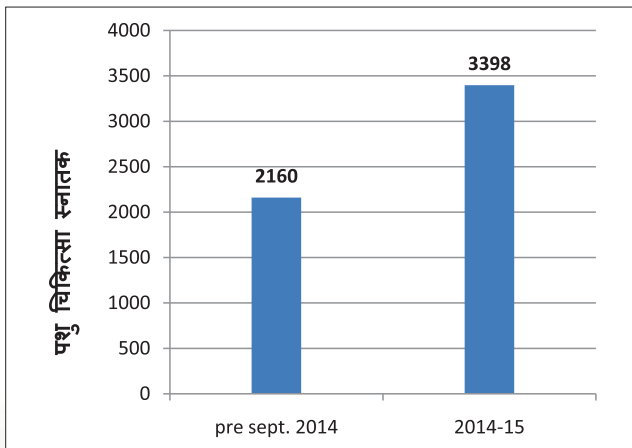
दस नये पशुचिकित्सा महाविद्यालय की बीवीएससी और एच अर्हता को मान्यता दी गई है और आईवीसी अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची में शामिल महाविद्यालय की संख्या 36 से बढ़कर 46 हो गई है।

17 पशु चिकित्सा महाविद्यालय की सीटों में बढ़ोत्तरी



प्रशिक्षित पशुचिकित्सों की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्ना पशुचिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों की संख्या को 60 से बढ़ाकर 100 किया गया था। 17 पशुचिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों की कुल संख्या को 914 से बढ़ाकर 1,334 किया गया है।

पशु चिकित्सा स्नातकों की संख्या में वृद्धि

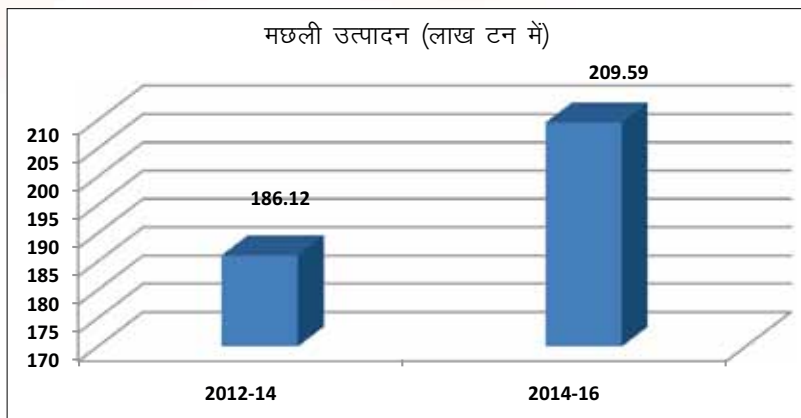


आईवीसी अधिनियम, 1984 की प्रथम अनुसूची में 10 और अधिक महाविद्यालयों के समावेशन के परिणामस्वरूप इन महाविद्यालयों से उत्तीर्ण हुए 3,398 विद्यार्थियों की बी.वी.एससी अर्हता को मान्यता दी गई है।

“कार्य करने में आसानी” के अंतर्गत पहलें

- ◆ दिल्ली, मुम्बई, कोलकत्ता चेन्नई, हैदराबाद, और बैंगलूर के सभी छह पशु संगरोध और प्रमाणन सेवा केंद्रों द्वारा पशुधन और पशुधन उत्पादों की ऑन-लाइन निकासी के लिए एकल खिड़की प्रणाली का कार्यान्वयन।
- ◆ पशुधन उत्पादों के आयात के लिए एसआईपी आवेदनों की ऑन-लाइन प्राप्ति और कार्यवाही हेतु सेन्ट्री आयात परमिट (एसआईपी) 01.10.2016 से पूर्ण रूप से लागु किया गया।

मात्स्यिकी - नीली क्रांति

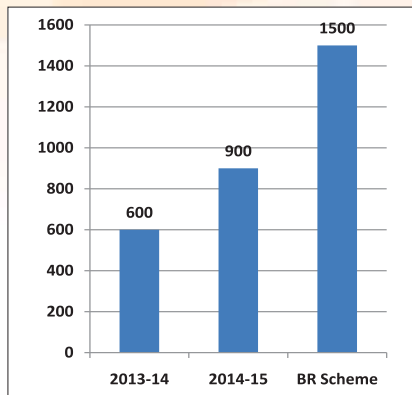
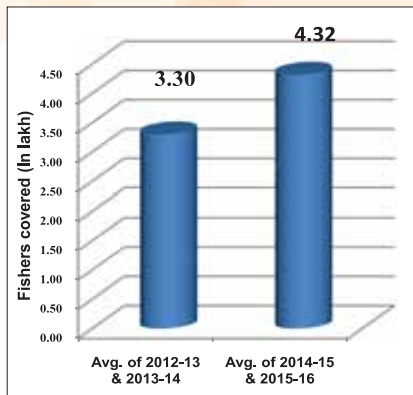


वर्ष (2012-14) की अपेक्षा वर्ष (2014-16) में वृद्धि दर 12.61% रही।
वर्ष 2015-16 के दौरान मछली उत्पादन में वार्षिक वृद्धि दर 6.21% है।

बचत-सह-राहत

Comparison of fishers covered for Saving-cum-Relief under the CSS on National Scheme for Welfare of Fishermen

बचत-सह-राहत राशि में वृद्धि की गई



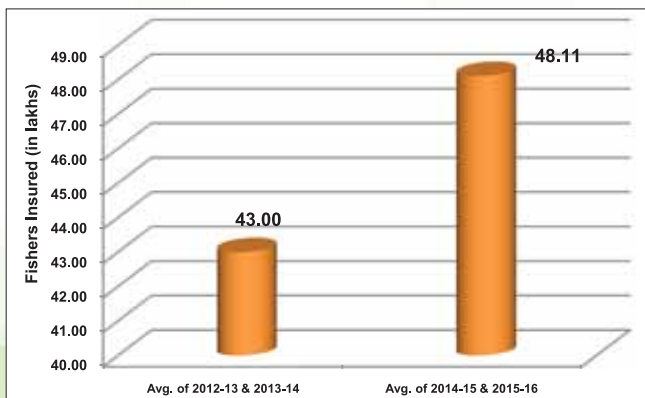
मात्स्यिकी का समेकित विकास और प्रबंधन के अंतर्गत— मत्स्य कम उत्पादन/प्रतिबंध मत्स्य वाले समय के दौरान मछुआरों को उपलब्ध कराई गई राशि में वृद्धि हुई।

2013-14: रु 600 प्रति माह

2014-15: रु 900 प्रति माह

BR Scheme: रु 1500 प्रति माह

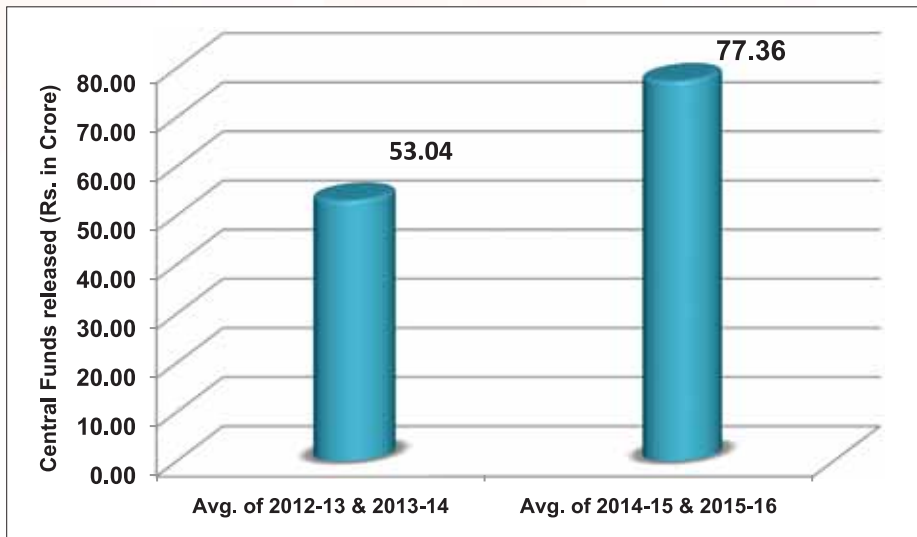
राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना पर सीएसएस के अंतर्गत बीमित मछुआरों की तुलना



मछुआरा बीमा योजना के अंतर्गत उपलब्धियां

- ◆ मछुआरा समुदाय के लिए वार्षिक बीमा प्रीमियम को 29.00 रु. से कम करके 20.34 रु. किया गया।
- ◆ दुर्घटना मृत्यु और स्थायी अपंगता के लिए बीमा कवर को 1.00 लाख से बढ़ाकर 2.00 लाख किया गया।

मात्स्यिकी अवसंरचना के विकास के लिए निर्मुक्त केन्द्रीय निधियों में तुलना



मात्स्यिकी अवसंरचना का विकास नीली क्रांति योजना के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। मात्स्यिकी अवसंरचना में मात्स्यिकी हार्बर/मछली लदान आदि शामिल है।

21 नवम्बर 2016 को विश्व मात्स्यिकी दिवस का आयोजन



पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग में 21 नवम्बर, 2016 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में विश्व मात्स्यिकी दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। 400 से अधिक प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया था जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी, मछुआरे, मत्स्य पालक, मात्स्यिकी सहकारिताओं के प्रतिनिधि, उद्यमी/निर्यातक तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी शामिल थे।

14 अक्टूबर, 2016 को विश्व अंडा दिवस मनाया गया



पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने अंडे के पौषणिक मान के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा मानव पोषण में इसके महत्व को रेखांकित करने के लिए 14 अक्टूबर, 2016 को 'विश्व अंडा दिवस' समारोह का आयोजन किया। लगभग 250 कुक्कुट पालकों को इसमें आमंत्रित किया गया।

26 नवंबर, 2016 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया



भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वर्गीज कुरियन के जन्मदिन को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का आयोजन दिनांक 26 नवंबर, 2016 को नारक कॉम्प्लेक्स, पूसा, नयी दिल्ली में किया गया। इस अवसर पर देश भर से वैज्ञानिक, अधिकारी एवं दुग्ध परिसंघों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर पहली बार ई-पशुहाट पोर्टल लॉन्च किया गया।



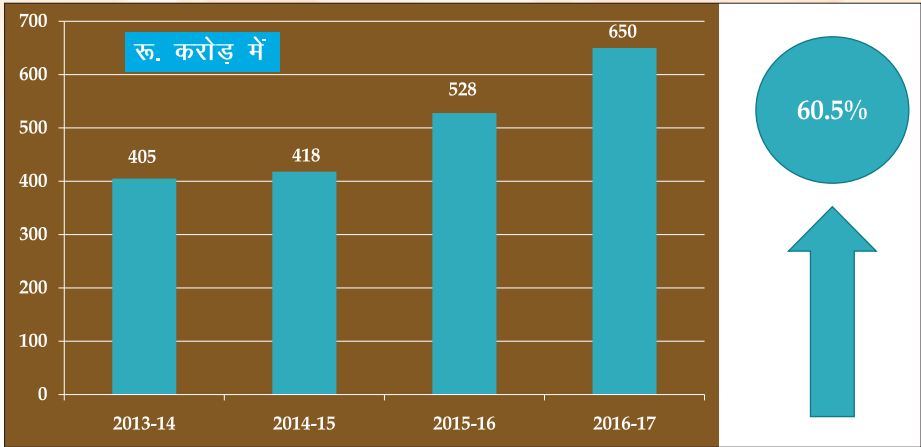
**कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद**



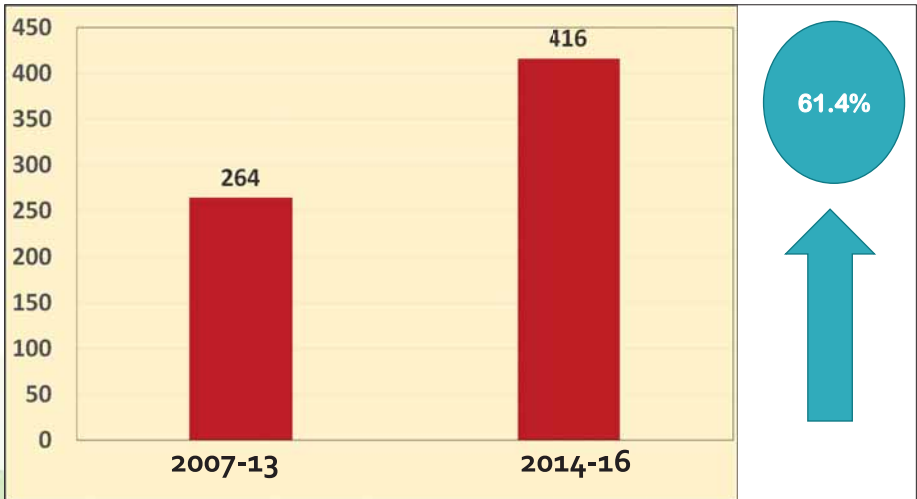
भारत
ICAR



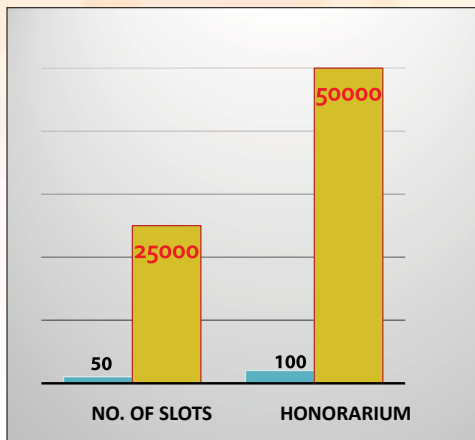
कृषि शिक्षा का बढ़ता हुआ बजट



कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवीणता विकसित करने हेतु नई प्रयोगात्मक इकाइयों की स्थापना

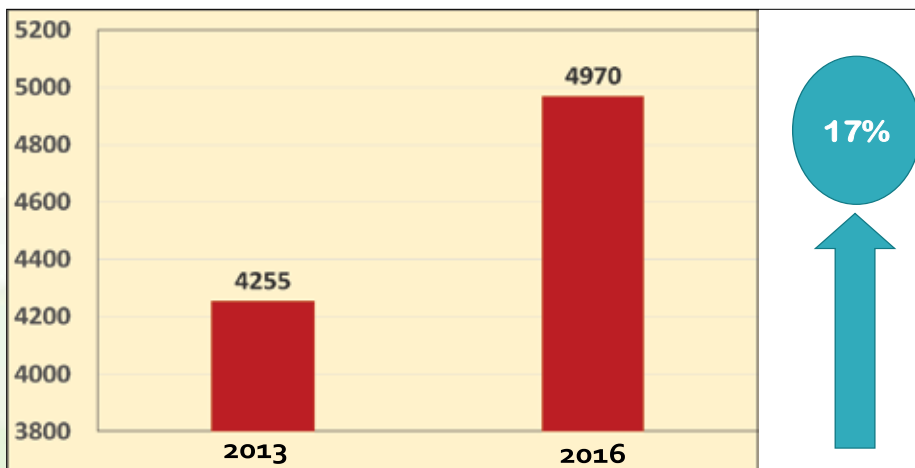


एमरेटस वैज्ञानिकों के सेवा शर्तों एवं संख्या में सुधार

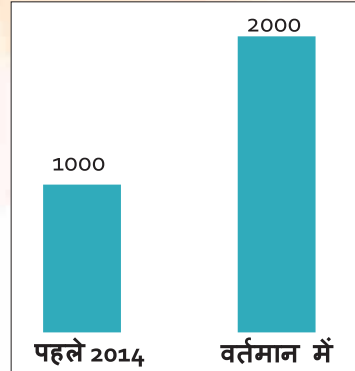


- ◆ स्लॉट की संख्या को 50 से बढ़ाकर 100 किया गया
- ◆ मानदेय की राशि रु. 25,000 से बढ़ाकर 50,000 की गई

परिषद ने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रवेश संख्या में वृद्धि की

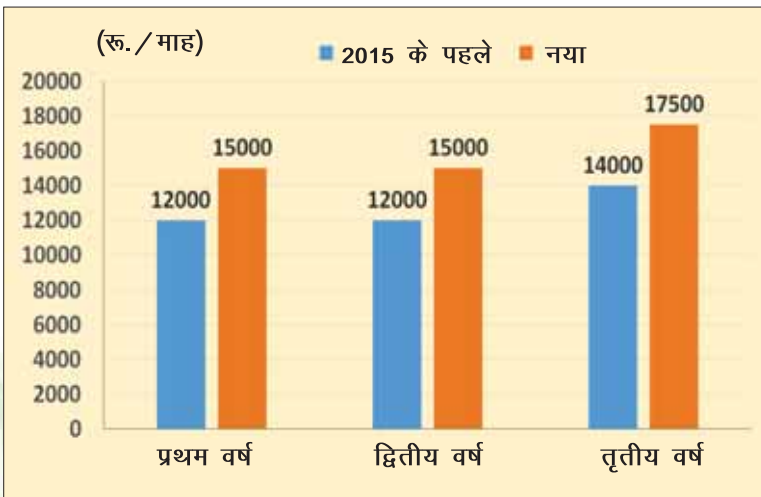


स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति को दोगुना किया गया



- ◆ ₹. 1000 प्रतिमाह से ₹. 2000 प्रतिमाह
- ◆ लाभार्थियों की सं: 1351

अनुसंधान अध्येताओं की फ़ैलोशिप बढ़ाई गई



पांचवीं अधिष्ठाता समिति द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम विकास

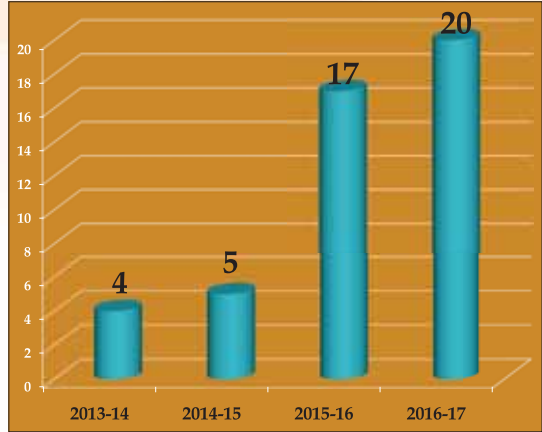


पांचवीं डीन समिति की रिपोर्ट का अनुमोदन 29 जून, 2016

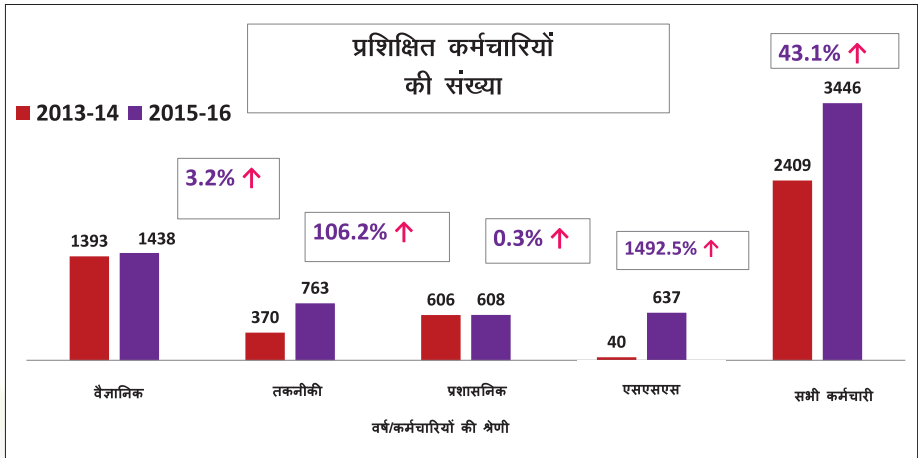
- ◆ शुरू किए गए नए कार्यक्रम
 - ◆ बी.टेक (जैव प्रौद्योगिकी)
 - ◆ बी.एससी. समुदाय विज्ञान
 - ◆ बी.एससी. खाद्य पोषण और आहारिकी
 - ◆ बी.एससी. रेशम कीटपालन
- ◆ कृषि विज्ञान में प्राप्त की गई डिग्रियों को व्यावसायिक घोषित किया गया
- ◆ स्नातक में पाठ्यक्रमों का सर्वांगीण वितरण
 - ◆ पहले वर्ष में पारम्परिक पाठ्यक्रम
 - ◆ दूसरे वर्ष में प्रौद्योगिकी आधारित पाठ्यक्रम
 - ◆ तीसरे वर्ष में प्रतिभा आधारित पाठ्यक्रम
 - ◆ चौथे वर्ष में व्यवसाय आधारित पाठ्यक्रम
- ◆ अनिवार्य सामान्य पाठ्यक्रम शुरू किए गए

कृषि विश्वविद्यालयों को अधिकारिक मान्यता प्रदान करना

मान्यता प्रदान किए गए विश्वविद्यालयों की संख्या



परिषद के कर्मचारियों का क्षमता विकास

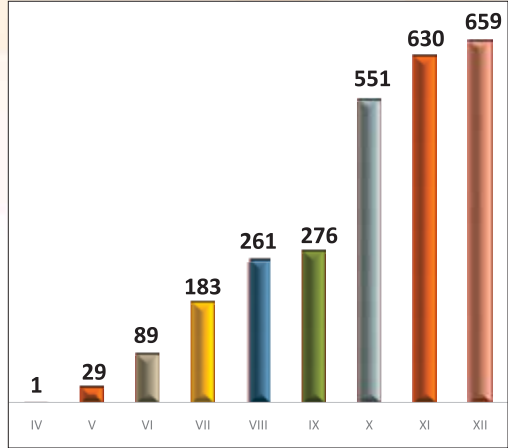


कृषि विज्ञान केन्द्रों का विकास

अवधि स्थापित किए गए
नए कृषि विज्ञान केन्द्र

2014-16	22
2012-14	7

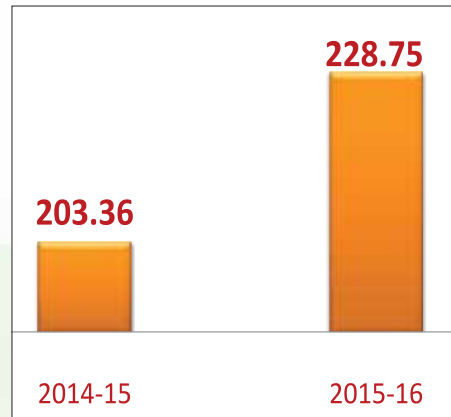
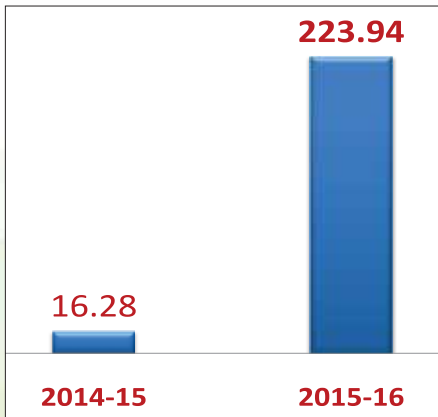
विभिन्न पंचवर्षीय योजना के
तहत के अंत में केवीके संख्या
में बढ़ोतरी



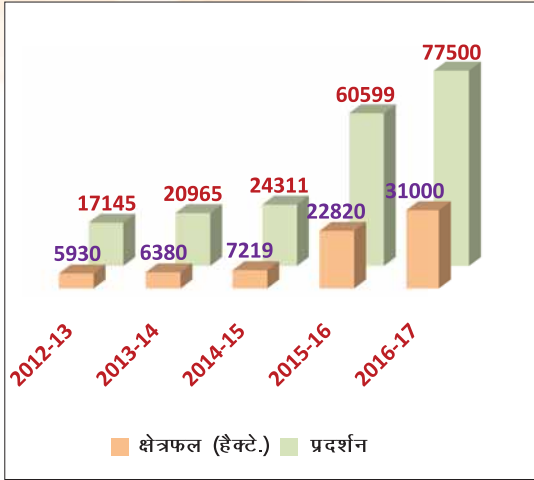
केवीके की उपलब्धियां

मोबाइल कृषि परामर्श (लाख)

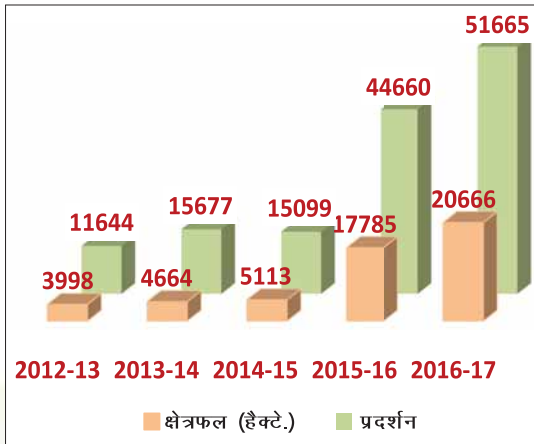
उत्पन्न की गई रोपण सामग्री (लाख)



केवीके द्वारा दलहन प्रदर्शन

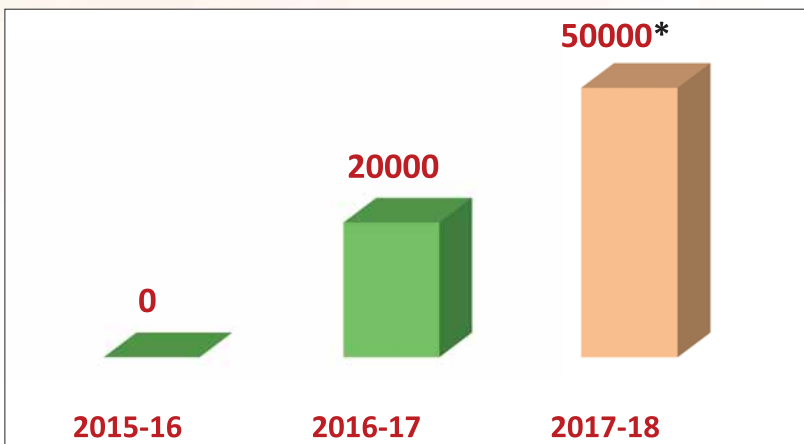


केवीके द्वारा तिलहन प्रदर्शन



पहले किसान (फार्मर फर्स्ट) ज्ञान वृद्धि एवं प्रौद्योगिकियों का समावेश

कृषि परिवारों की संख्या

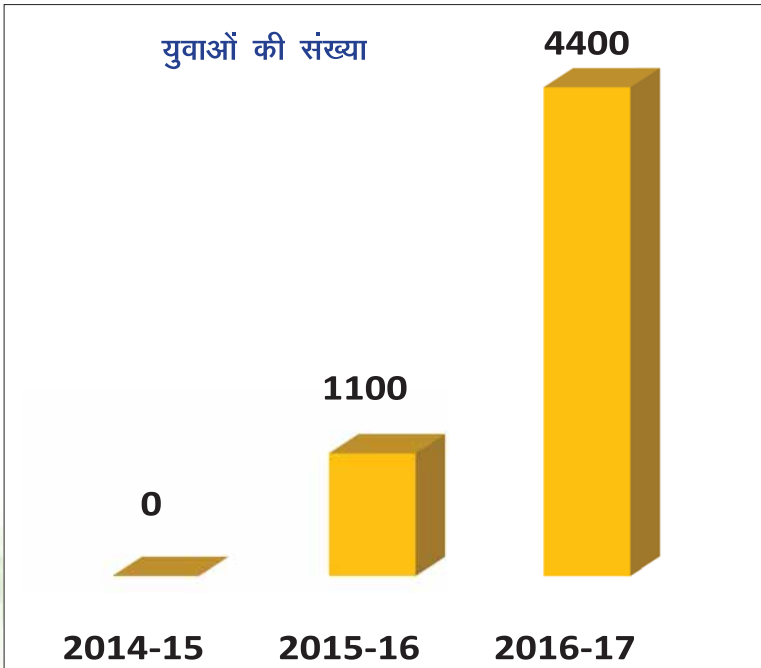


- ◆ फार्मर-वैज्ञानिक – इंटरफेस बढ़ाना
- ◆ तकनीक को एकत्रित करना, उसका अनुप्रयोग और फीडबैक
- ◆ सहभागिता और संस्था निर्माण
- ◆ विषयवस्तु को एकत्रित करना
- ◆ भा.कृ.अ.प. के संस्थानों/कृषि विश्वविद्यालयों को 13.09 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ स्वीकृत 33 परियोजनाएं
- ◆ 2017-18 के दौरान शामिल किए जाने वाले 50000* परिवार



युवाओं को कृषि की तरफ आकर्षित कर उनकी अभिरूची बनाए रखना (आर्या)

- ◆ ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को विभिन्न कृषि और सम्बद्ध और सेवा क्षेत्रों के उद्यमों की ओर आकर्षित करना और उन्हें सशक्त बनाना
- ◆ प्रसंस्करण मूल्यसंवर्धन, मार्केटिंग और नेटवर्किंग पर बल
- ◆ उद्यमिता विकास और मूल्य श्रृंखला प्रबंधन
- ◆ 25 राज्यों में 25 कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से प्रति जिला 200–300 युवा शामिल हैं

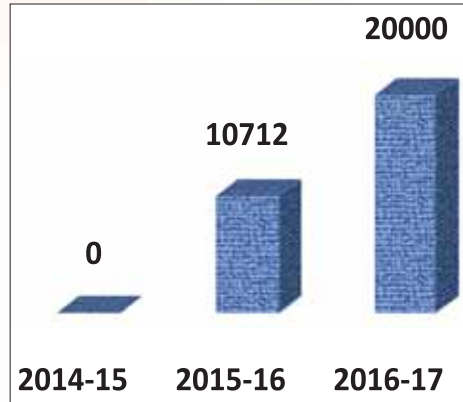




मेरा गांव मेरा गौरव

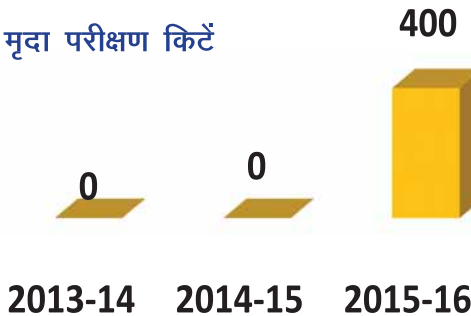
- ◆ पहचाने गए 5 गांवों के साथ 4 वैज्ञानिकों का समूह कार्य कर रहा है
- ◆ किसानों को जानकारी, दक्षता और सूचना देने में सहायता देना
- ◆ चेतावनियां और परामर्श समय पर जारी करना
- ◆ निवेशों, सेवा प्रदाताओं के बारे में सूचना उपलब्ध कराना,
- ◆ गांवों के विकास के लिए विभिन्न विभागों और संगठनों के साथ अभिसरण विकसित करना

गांवों की संख्या



मृदा स्वास्थ्य

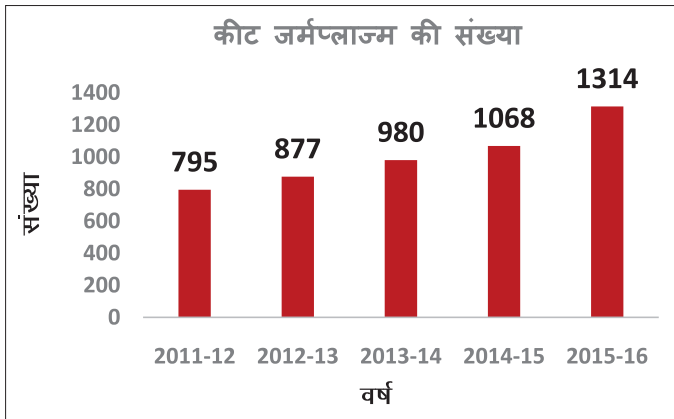
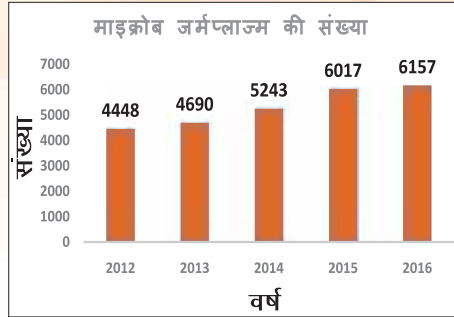
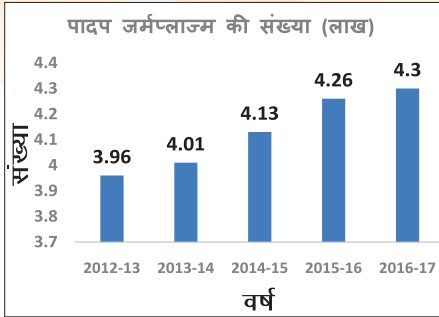
मृदा परीक्षण किटें



- ◆ 2015-16 के दौरान 400 मृदा परीक्षण किटें उपलब्ध कराई गईं
- ◆ 2016-17 के दौरान 250 मृदा परीक्षण किटें अनुमोदित की गईं

- ◆ 2015- नवम्बर 2016 के दौरान 2.5 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए
- ◆ 5 दिसम्बर, 2016 को 1.21 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए

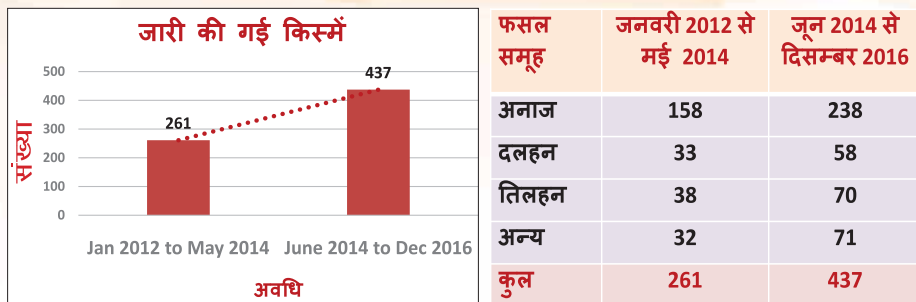
आनुवंशिक संसाधनों का प्रबंधन



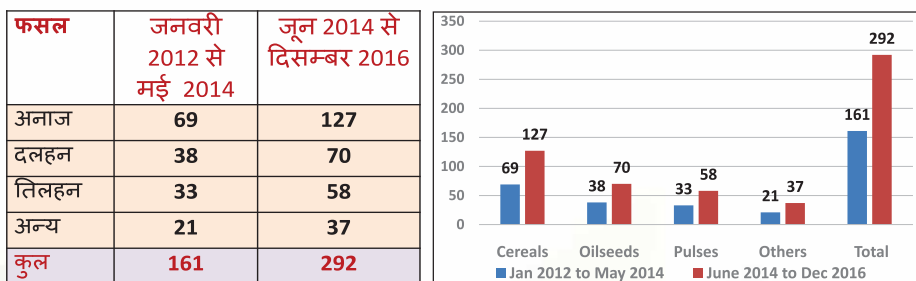
2014 से जोड़े गए आनुवंशिक संसाधन

- ◆ 29000 पादप जर्मप्लाज्म
- ◆ 1467 माइक्रोब जर्मप्लाज्म
- ◆ 334 कीट जर्मप्लाज्म

पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी की गई फसल किस्में

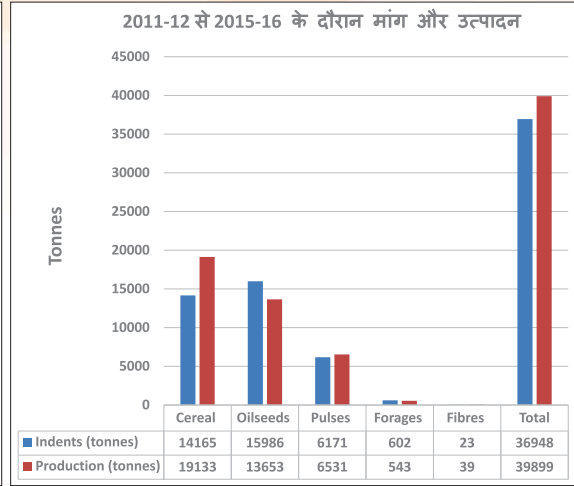
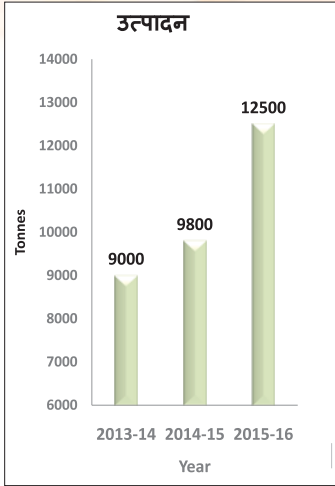


जलवायु अनुकूल अजैविक प्रतिबल की प्रतिरोधी/सहिष्णु जारी की गई किस्मों की संख्या



प्रजनक बीज उत्पादन

अधिकांश फसलों में प्रजनक बीज उत्पादन मांग से कहीं अधिक था



1966 से 2016 की अवधि के दौरान बागवानी फसलों की अधिसूचित किस्में

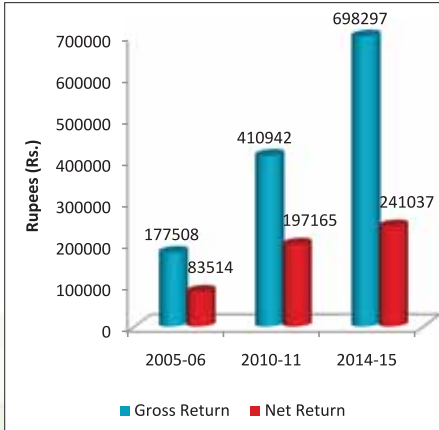
जिंस	1966-2002 (36 वर्ष)	2003-2007 (4 वर्ष)	2008-2013 (5 वर्ष)	2014-16 (2 वर्ष)
फल	3	14	2	8
सब्जी (आलू और प्याज सहित)	370	169	83	74
मसालें और कॉडिमेंट्स	0	14	11	18
रोपण फसलें	3	0	9	8
फूल	4	5	1	4
औषधीय और सगंधीय पौधे	1	0	7	1
कंद और राइजोम्स	29	8	2	2
कुल	410	210	115	115

कृषि आय को दोगुना करने के लिए समेकित कृषि प्रणाली मॉडल



घर का आकार: 1.20 है.,
7 सदस्यीय परिवार

फील्ड फसलें	0.84 है०
बागवानी फसलें	0.22 है०
डेरी	2 भैंस + 1 गाय
मात्स्यिकी	0.10 है०
वर्मी-कम्पोस्ट	0.01 है०
मशरूम	12 सं० 4 टियर रैक्स
सीमा रोपण (200 मी. रनिंग लम्बाई)	

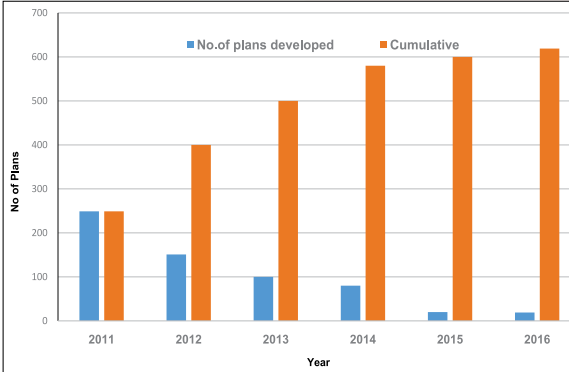


- ◆ देश के विभिन्न कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों के लिए 45 आईएफएस मॉडल विकसित किए गए
- ◆ आईएफएस को लाभप्रदता, आजीविका सृजन और जोखिम को कम करने के साथ जोड़ा गया
- ◆ आईएफएस चरम मौसम की घटनाओं के वर्षों के दौरान भी स्थायी आय उपलब्ध कराते हैं
- ◆ बहु-उद्यम आईएफएस को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता समर्थित स्कीम

- ◆ निवल लाभ (3 वर्षों का माध्य): 2014-15 के दौरान रु. 2.5 लाख
- ◆ पुनःचक्रण: श्रम को छोड़कर अन्य सभी निवेशों का 34%
- ◆ अतिरिक्त रोजगार का मूल्य : रु. 88,000

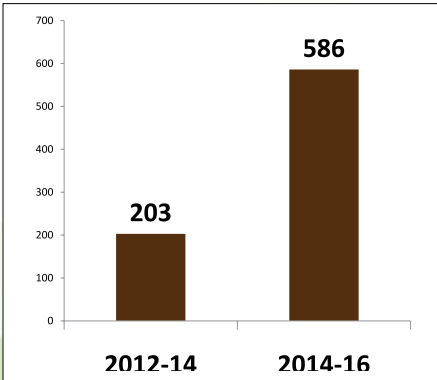
जिलों के लिए आकस्मिक योजनाओं का विकास

619 जिलों की कृषि संबंधी आकस्मिक योजनाएं तैयार की गईं: बागवानी, पशुधन, पोल्ट्री, मात्स्यकी सहित कृषि के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए अनेक प्रकार की मौसम असामान्यताओं के लिए प्रौद्योगिकीय युक्तियां

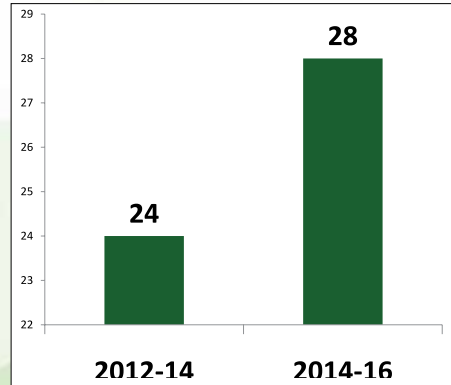


उद्यमशीलता विकास

इनक्यूबोटेड कृषि- उद्यम



संस्थापित कृषि-प्रसंस्करण केन्द्र



भारत का पशु आनुवांशिक संसाधन- वर्तमान परिदृश्य

प्रजातियाँ	नस्लों की संख्या
गोपशु	40
भैंस	13
बकरी	26
भेड़	42
ऊँट	9
घोड़ा	6
सूअर	6
गधा	1
चिकन	17
कुल	160



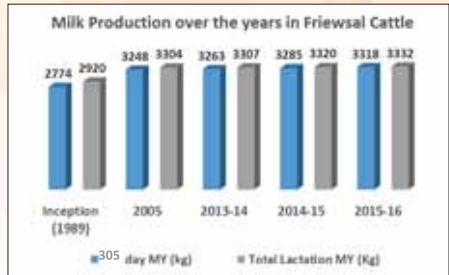
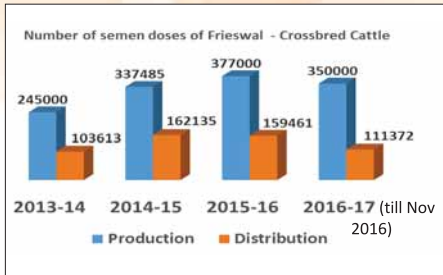
पंजीकृत नए पशुधन तथा पोल्ट्री नस्लों



- ◆ वर्ष 2014–15 में 7 नई देसी नस्लों पंजीकृत की गईं
- ◆ वर्ष 2015–16 में 9 नई देसी नस्लों पंजीकृत की गईं

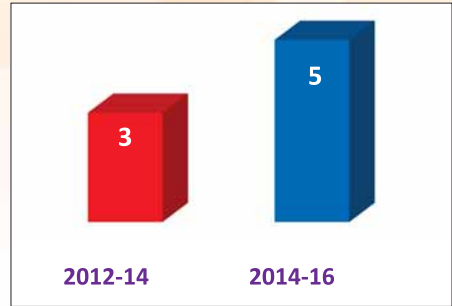


प्रौद्योगिकी उपयोग का प्रभाव



रोगों की रोकथाम हेतु विकसित वैक्सीन

- ◆ जोहन रोग
- ◆ पैस्ट डिस पेटिटिस रूमिनेन्ट्स (पीपीआर)
- ◆ गोट बौक्स
- ◆ इक्यूहरपेबोर्ट
- ◆ क्लासिकल स्वाइन फीवर

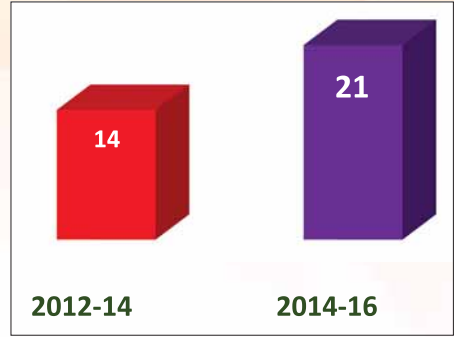


विकसित की गई रोग-निदान किट

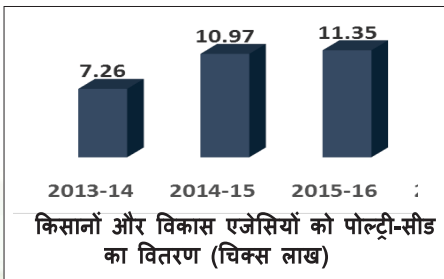
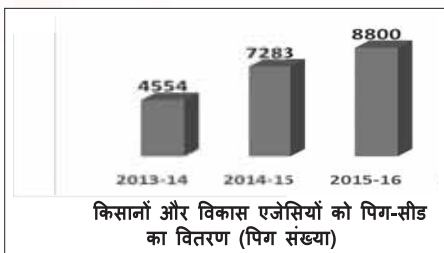
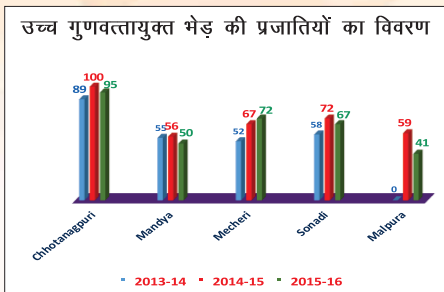
- ◆ इलिसा किट – की थीलिरिया इक्वी
- ◆ इलिसा किट– जेपनिस इनसिफेलिटिस
- ◆ लेटरल फ्लो एसे – ब्रुसिलोसिस
- ◆ लेटरल फ्लो एसे– ट्राम्पेनोसामा इवानसी
- ◆ पेपर – स्ट्रिप एसे– दुध में

कीटनाशक अपशिष्ट

डीबीटी– ब्रुसिलोसिस निदान इलिसा किट विकसित करने के लिए निवीडे (एनआईवीईडी. आई) को “बायोटेक प्रोडक्ट” पुरस्कार

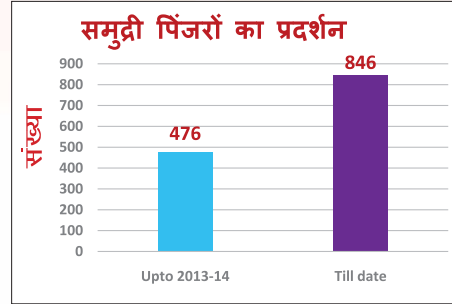


उच्च गुणवत्ता युक्त पशुधन जननद्रव्य का वितरण



खुले समुद्र में पिंजरों में जलजीवन पालन

- ◆ कोबिया (रेचीसेन्द्रोन कैनाडम) तथा सिल्वर पोम्पेनो (ट्रैचीनोटस ब्लोची) का समुद्री पिंजरा पालन- प्रौद्योगिकी प्रदर्शन
- ◆ 6 माह में 3.0 टन के औसत उत्पादन का प्रदर्शन (6 m dia x 6 m depth) : 25-30 kg/m³
- ◆ उत्पादन लागत रूपए 120 / कि. ग्रा. फार्म गेट मूल्य रू. 350 / कि. ग्रा. (कोबिया) तथा रू. 300 क्रि. ग्रा. (सिल्वर पोम्पेनो)
- ◆ भाकृअप- सीएमएफआरआई की तकनीकी सहायता से भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में 846 पिंजरे स्थापित किए गए

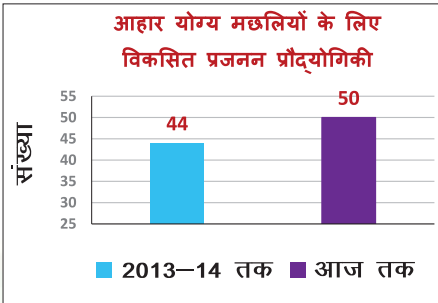


समुद्री पिंजरा पालन के लिए विविधीकृत मछली प्रजातियां

- ◆ खुले समुद्र में पिंजरा पालन के लिए व्यवसायिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री प्रजातियों के लिए विकसित की गई प्रजनन और बीज उत्पादन प्राद्योगिकी
 - ◆ कोबिया (रैयीसेनट्रोन केनाडम)
 - ◆ सिल्वर पोम्पेनो (ट्रैयीनोटस ब्लोची)
 - ◆ ओरेंज स्पॉटिड ग्रुपर (ईपीनिफेलस कोइओडेस)



आहार योग्य 6 नई मत्स्य प्रजातियों के लिए प्रजनन तथा बीज उत्पादन प्राद्योगिकी विकसित की गई।



मत्स्य स्वास्थ्य प्रबंधन

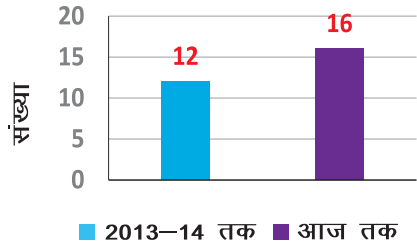
- ♦ राष्ट्रीय जलजीव पशुरोग निगरानी कार्यक्रम (एनएसपीएएडी) का संचालन –115 जिलों में 15 राज्य तथा 2 संघ शासित राज्य
- ♦ एनएसपीएएडी के तहत रैफरल प्रयोगशालाओं तथा आपातकालीन कार्रवाई प्रणाली की स्थापना के साथ उभरते रोग प्रकोप के लिए तैयारी।
- ♦ 50 सैल- लाईन्स वाली फिश सैल लाईन्सों की राष्ट्रीय रिपोजिट्री की स्थापना

रोग निदान किट का विकास (संख्या 4)

- ♦ समुद्री फिन-फिश में B नोडावायरस का पता लगाने के लिए – β Nodadetect
- ♦ श्रिम्प के लिए सफेद धब्बा सिंड्रोम वायरस का पता लगाने के लिए किट
- ♦ मीठे जल की मछली में कोई हरपिस वायरस (केएचवी) तथा कार्य वायरस का स्प्रिंग विरामिया (एसवीसीवी)

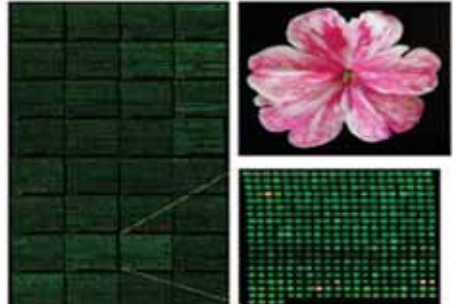


विकसित नैदानिक किट



अतिविशिष्ट उपलब्धियाँ

- ◆ मृदा परीक्षक, मृदा विश्लेषण हेतु एक सूक्ष्म प्रयोगशाला, एसएचसी के 12 मृदा प्राचलों (पीएच, ईसी, ओसी, उपलब्ध एन, पी, के, एस तथा एफई, जैडएन, सीयू, एमएन एवं बी) के आमापन में सक्षम
- ◆ भारत का प्रथम नैनोसेल्यूलोज पायलट संयंत्र, सीआईआरसीओटी, मुम्बई में स्थापित, प्रकृतिक रबर, क्राफ्ट पेपर एवं फिलर अथवा कम्पोजिट मिक्स के रूप में सीमेंट कंक्रीट के उत्पादनार्थ
- ◆ बहुपादप विषाणु पहचान प्रौद्योगिकी का विकास, इस आणविक निदान सूचक प्ले. टफार्म पर 1155 विषाणुओं की एक साथ पहचान करने में सक्षम
- ◆ मिल्क फिश (*चानोस चानोस*), हिल्सा (*टेन्यूआलोसा इलीशा*) एवं लॉग व्हिस्कर्स कैटफिश (*मिस्टस गूलियो*) के प्रजनन एवं बीजोत्पादन में बड़ी सफलताएं प्राप्त की गई हैं।



दालों में आत्मनिर्भरता लाने हेतु अतिविशिष्ट नवीन विकास: विश्व में अपने प्रकार का प्रथम

- ◆ सबसे अगेती परिपक्व होने वाली मूंग की किस्म, "आईपीएम 205-7 (विराट)" जारी की गई
- ◆ सबसे अगेती परिपक्व होने वाली (52-55 दिन) ग्रीष्मकालीन मूंग की किस्म
- ◆ 10-12 क्विं/हे उपज क्षमता
- ◆ मूंगबीन यलो मोजायक विषाणु रोग एवं अन्य रोगों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी



सीओ-0238: गन्ने की एक बहुत अच्छी किस्म

- ◆ उत्तर भारत में गन्ने की अन्य किस्मों (9% तक) की तुलना में चीनी की अधिक प्राप्ति (12% तक)
- ◆ अधिक गन्ना उपज (81 टन/ हे)



प्रवृत्ति में उलटाव: पहली बार यह देखा गया है कि इस उपोष्ण कटिबंधीय किस्म के बीज की मांग, उष्ण कटिबंधीय राज्यों जैसे कि, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में भी है

अधिक सेब उत्पादन हेतु उच्च घनत्व रोपण एवं कैनोपी प्रबंधन

- ◆ रोपण: उच्च घनत्व (2.5मी x 2.5मी)
- ◆ वृक्ष ट्रेनिंग: नियमित वार्षिक कटाई—छंटाई के संयोजन में रूपांतरित सेन्ट्रल लीडर सिस्टम



- ◆ बूंद—बूंद सिंचाई तथा संस्तुत खादें, ऊर्वरक एवं पादप सुरक्षा
- ◆ वर्तमान 7.5 टन/हे उत्पादिता में 30—35 टन/हे तक बढ़ोत्तरी



जलसंभरों में जलदोहन हेतु बहुउद्देशीय रबर बांध

- ◆ जल संभर हेतु बहुउद्देशीय, फुलाए जाने योग्य, लचीले रबर बांध विकसित किए गए।
- ◆ पारंपरिक चौक बांध की तुलना में, इनमें 20—25% अतिरिक्त जल का भंडारण किया जा सकता है।
- ◆ भूजल रीचार्जिंग में सहायक है।
- ◆ फसल वृद्धि की क्रांतिक अवस्थाओं में सिंचाई उपलब्ध कराता है
- ◆ लागतरु लगभग 8 लाख रूपए (चौड़ाई 5 मी X 1.5 मी ऊंचाई)

- ◆ तीन वर्षों की अवधि के भीतर लागत की पुनर्प्राप्ति
- ◆ 6 राज्यों (ओडिशा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, एवं झारखंड) में 43 रबर बांध बनाए गए



प्रमुख विकसित उन्नत कृषि मशीनरी

- ◆ चौड़ी क्यारी बनाने वाला- एंव- बीजक
- ◆ बाग-प्रबंधन हेतु बहुउद्देशीय प्लेटफार्म बाग- प्रबंधक
- ◆ गन्ने के लिए एकल कलिका कर्तक मशीन एवं एकल कलिका स्थिरण रोपक



प्रमुख विकसित फसल किस्में तथा प्रौद्योगिकियां

- ◆ मार्कर की सहायता से चयन का उपयोग करते हुए सूखा (1), ब्लास्ट (3) तथा जीवाणु पर्ण झुलसा (5) प्रतिरोधी चावल की उच्च पैदावार वाली किस्में विकसित की गईं
- ◆ उच्च प्रोटीन अंश वाली (10.3%) चावल की किस्म (सीआर धान 310) विकसित की गईं
- ◆ उच्च जिंक अंश (22पीपीएम) युक्त चावल की किस्म (डीआरआर धान 45) विकसित की गईं
- ◆ दोहरे प्रयोजन वाली गेहूं (दाना एवं चारा) की किस्म (वीएल गेहूं 829) विकसित की गईं
- ◆ कम इरुसिक अम्ल (<2%) सरसों की किस्म, पूसा सरसों 30 विकसित की गईं



निर्यात हेतु विकसित चुनिन्दा उन्नत फल-किस्में



अंगूर



मंजरी नवीन : सेल्फ थिनिंग एंड बोल्ड बेरीज

मेडिका : प्रचुर मात्रा में प्रति- ऑक्सीकारक



काजू



बड़ी गिरी (11-12 ग्राम) के साथ काजू संकर किस्म (एच-126)

प्रमुख विकसित उन्नत बागवानी किस्में

- ◆ लालिमा, उच्च पैदावार वाली क्रिमसन रंगदार सेब की किस्म
- ◆ धवल, बड़े आकार वाली और स्वादिष्ट अमरुद की किस्म
- ◆ अर्का किरण, उच्च लाईकोप्रिटिन अमरुद संकर किस्म
- ◆ तमिलनाडु के लिए उच्च पैदावार वाली नारियल संकर किस्म (वीपीएम-5)



असाधारण सब्जी फसल किस्में और प्रौद्योगिकियां

- ◆ एक बिटा कैरोटिन (8.0 –10.0 पीपीएम) बंद गोभी की उन्नत किस्म (पूसा केसरी वीआईटी ए-1) विकसित की गई
- ◆ संरक्षित खेती के लिए अतिरिक्त अगेती ककड़ी/खीरा किस्म (पूसा बीज रहति कुकुम्बर – 6) जारी की गई
- ◆ उच्च पैदावार वाली चूर्णी फफूंद प्रतिरोधी काली तोरी किस्म (वीआरआरजी-27) विकसित की गई
- ◆ मध्यम अवधि (50 दिन) के लिए नई उच्च पैदावार वाली आलू किस्म कुफरी मोहन विकसित की गई



विशिष्ट जरूरतों के लिए सब्जी की किस्में

प्याज: अर्का कल्याण, अर्का स्वादिष्ट, अर्का बिंदु, अर्का उज्ज्वल



खुंबी- वंशावली:

शाइटेक डीएमआर-शाइटेक-38
डीएमआर-शाइटेक -388
मेक्रोसाइब डीएमआर-मेक्रोसाइव-01



टमाटर: अर्का रक्षक, अर्का सम्राट



जैव-नियंत्रण में सफलता की गाथाएं

प्राप्त सफलता	प्राकृतिक शत्रु	भारत में मौद्रिक लाभ (रूपये)/वर्ष
• गन्ने में वूली एफिड	<i>डीफा / इनकर्सिया / माइक्रोमस</i>	1500 करोड़
• पपीते में मीलीबग	एक्रोफगुस	1600 करोड़
• सुपारी, गन्ने और मूंगफली में रूट ग्रब	इंटोमोपेथोजेनिक नेमाटोड	300 करोड़
• गन्ने और चावल में बोरर	<i>ट्राइकोग्रामा</i>	37500 / हैक्टेयर

प्राकृतिक शत्रु



इनकर्सिया फ्लेवोसकुटेलियम वूली एफिड पारासिटोयड



हिटरोरोबडिटिस इंडिका



एक्रोफगुस पपैयाई-स्थानिक पपैया मीलीबग का पारासिटोयड

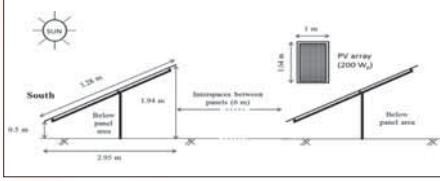


ट्राइकोग्रामा काइलोसिस गन्ना और चावल बोरर

कृषि-वोल्टीय प्रणाली/सौर कृषि

कृषि-वोल्टीय प्रणाली

एक भूखंड से माड्यूलों के माध्यम से उगती फसलें और साथ-साथ बिजली का सृजन



मॉडल क्षेत्र: 1 हैक्टेयर

- ◆ सौर जीवी उत्पादन क्षमता: 0.5 मेगावाट
- ◆ प्रतिदिन बिजली उत्पादन: 2500 कि.वा.
- ◆ निवेश: 2.5 करोड़ रुपये
- ◆ बिजली से आय सृजन: लगभग 45 लाख रुपये प्रति वर्ष
- ◆ प्रणाली की मियाद: 25 वर्ष
- ◆ 7 वर्ष में लागत की कुल रिकवरी
- ◆ मूंग की उपज: 4 क्विंटल/हैक्टे.

सौर कृषि प्रणाली में स्वस्थाने मृदा नमी में कटक हल रेखा बीज ड्रिल



सौर कृषि प्रणाली में कृषि रसायनों के छिड़काव के लिए सौर पीवी स्प्रेयर का विकास



माइक्रो सिंचाई के माध्यम से जल/उर्वरक की बचत

केन्द्र	फसल	उपज (टन/हे.)	जल की बचत (%)	उर्वरक की बचत (%)
राहुरी	केला	83	25	17
परभनी	कपास	2.9	20	25
मदुरै	सूखी मिर्च	2.2	40	25
भवानीसागर	टमाटर	27	40	50
राहुरी	गन्ना	155	20	20

केन्द्र	फसल	उपज (टन/हे.)	उपज में बढ़ोतरी (%)	जल की बचत (%)
भटिंडा	लहसुन	13.1	18	23
गवाशपुर	प्याज़	16.0	22	25
बिलासपुर	गेहूँ	1.98	16	41
बेलवतागी	मक्का	8.28	21	12
श्रीगंगानगर	चना	2.57	14	32

सिंचाई	उपज (क्विं./हे.)	डब्ल्यू यूई (कि.ग्रा/हे.एमएम)	उपज में बढ़ोतरी (%)	जल की बचत (%)
प्याज़ में माइक्रो-छिड़काव सिंचाई				
बाढ़ सिंचाई	128.1	24.73	--	--
माइक्रो -छिड़काव	185.2	46.11	44.6	22.4

ड्रिप सिंचाई



छिड़काव सिंचाई



माइक्रो छिड़काव सिंचाई



पोषकों के उपयोग में अधिक दक्षता के लिए नैनो उर्वरकों का विकास

Zn की कमी वाले क्षेत्रों में फसल की Zn की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सफल विधि पाई गई 50 मि.ग्रा. / Zn ग्राम बीज की दर से नैनो-ZnO @ के साथ बीज का उपचार सूक्ष्मजीवी स्रावों का उपयोग करते हुए 4 जी-नैनो आधारित पोषिक कृषि निवेशों (फास्फोरस मैग्नेशियम, जिंक और आयरन)

सूक्ष्म पोषकों के उपयोग से दक्षता 1-2 % से बढ़कर 5-7 हो गई एसएसपी के साथ तुलनीय P उपयोग की दक्षता के साथ नैनो रॉक फॉस्फेट कोटिड यूरिया का विकास किया गया



सोयाबीन



मक्का



नई प्रौद्योगिकियों का विकास और व्यावसायिकरण



- ◆ जल की बचत करने और सिंचाई की अनुसूची तैयार करने में सहायता के लिए दक्ष और उपभोक्ता के अनुकूल इलेक्ट्रॉनिक मृदा नमी इंडीकेटर,
- ◆ मैसर्स टैक सोर्स सोलन, बेंगलुरु और अन्य को लाइसेंस दिया गया

- ◆ लाभकारी कीटों (पेरासिटोयड्स) और गैर-लक्षित कीटों के लिए सुरक्षित उन्नत लाइट ट्रेप
- ◆ 2014-16 के दौरान 3.02 करोड़ रुपये का राजस्व सृजित किया गया।



- ◆ स्वास्थ्यकर पेय के रूप में उपयोग के लिए गन्ने के जूस का पाउडर
- ◆ मैसर्स जी. बेवरेजिज, बेलगाम को लाइसेंस दिया गया



सूअर और कुक्कुट की नई उन्नत किस्मों का विकास

- ◆ सूअर की तीन नई संकर नस्लें नामतः रानी, आशा, एचडी-के75 तथा जहरसुक विकसित की गईं।
- ◆ कुक्कुट पक्षियों की तीन नई किस्में (कामरूपा, नर्मदानिधि और झरसिम) विकसित की गईं।



दक्षता में वृद्धि करने और लागत का कम करने के लिए देसी मछली आहार संरूपण

- ◆ वेन्नामई – पैसिफिक श्वेत श्रिम्प एल. वेन्नामई (वाणिज्यकृत)
- ◆ लागत लाभ – वाणिज्यक आहार पर 15 रुपये/किलोग्राम
- ◆ वाणिज्य आहार की लागत– 75 रु./कि.ग्रा.



वर्णा और वर्षा – समुद्री और मीठा जल सजावटी मछलियों के लिए आहार



सीफाब्रूड – कार्प ब्रूडस्टॉक आहार जो गोनाड से संवृद्धि और परिपक्व करता है

2016 में जलीय जीवों से न्यूट्रासियुटीकल्स का विकास

- मानव स्वास्थ्य के लिए उच्च मान वाले योगजों तथा न्यूट्रासियुटीकल का विकास:
 - ग्रीन मसल्स सांद्रण (केडालमिन^{टीएम} जी.एमई.)- दर्द और गठिया के लिए
 - ग्रीन शैवालीय सांद्रण (केडालमिन^{टीएम} जी.एई) - दर्द और गठिया के लिए
 - समुद्री खरपतवार मधुमेहरोधी सांद्रण (केडालमिन^{टीएम}- ए.डी ई) टाइप-2 मधुमेह के लिए एक हरी औषधि
 - समुद्री खरपतवार न्यूट्रासियुटीकल पेय - सूक्ष्म पोषकों में वृद्धि के लिए
 - समुद्री खरपतवार के साथ पोष्टिक बनाए गए मछली स्वेसेज



नई पीढ़ी के मछली पकड़ने वाले जलयान का विकास

- नई पीढ़ी की ईंधन दक्ष और बहुउद्देशीय मछली पकड़ने वाले जलयान का डिजाइन बनाया गया और उपयोग आरंभ किया गया

ट्रालिंग, गील नेटिंग और लांग लाइनिंग के लिए बहुउद्देशीय मछली पकड़ने का जलयान



नए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता



एनजीआरएयू, आंध्र प्रदेश और एसकेटीएलएसएचयू, तेलंगाना प्रत्येक को रूपये 122.5 करोड़ निर्गत किया गया

विश्वविद्यालय छात्रवृत्तियाँ



कृषि और संबद्ध विज्ञान में डिग्री को व्यावसायिक दर्जा प्रदान किया गया

एनएआरएसई तंत्र से उत्कृष्ट सेवानिवृत्त शिक्षकों/वैज्ञानिकों की सेवाओं के उपयोग हेतु विशिष्ट पाठ्यक्रम के शिक्षण और प्रशिक्षण संबंधी सामग्री के विकास के लिए एमीरीटस प्रोफेसर योजना 2016-17 की शुरु की गई। राष्ट्रीय टैलेंट छात्रवृत्ति- पीजी शुरु की गई जिसमें उन सभी छात्रों के लिए जो अपने डोमीसाइल राज्य से अलग किसी राज्य में नामांकन लेते हों, प्रतिमाह रू. 3000/- की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।

लाभार्थियों की संख्या- 1,512

स्टूडेंट रेडी

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 25 जुलाई 2015 को शुरू किया गया।

2016-17 से अभ्येतावृत्ति के रूप में सभी छात्रों के लिए स्टूडेंट रेडी के दौरान 6 माह के लिए 3000 रुपये प्रतिमाह की शुरुआत जो पहले 1000/-प्रति माह थी।

(स्टूडेंट रेडी के अंग)

1. अनुभवजन्य अधिगम (ईएल)
2. ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव (आरएडब्ल्यूई)
3. पौधा प्रशिक्षण/औद्योगिक जुड़ाव/प्रशिक्षण
4. कौशल विकास प्रशिक्षण
5. छात्र परियोजना



नेताजी सुभाष-आईसीएआर अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

- ◆ विश्व के चयनित सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित सक्षम मानव संसाधन का विकास करना। - 79 छात्र
- ◆ आईसीएआर- कृषि विश्वविद्यालय तंत्र में विदेशी अभ्यर्थियों को भारत के सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालयों के सुगम्य बनाना जिससे वर्धित भविष्य सहयोग हेतु वैज्ञानिक- दूत का एक पूल तैयार हो। - 23 छात्र



वार्षिक 30 अभ्येतावृत्ति

- ◆ यूएस डॉलर 2000 प्रतिमाह (भारतीय अभ्यर्थियों के लिए) और
- ◆ रू 40000/- प्रतिमाह (विदेशी अभ्यर्थियों के लिए)
- ◆ नए (फ्रेश) और सेवारत (आईसीएआर- राज्य कृषि विश्वविद्यालय)

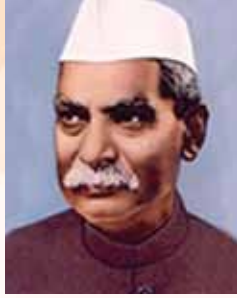


चार नए आईसीएआर पुरस्कार

पुरस्कार का नाम (संख्या)	शुरूवात का वर्ष	पुरस्कार का मूल्य
1) आईसीएआर प्रशासनिक पुरस्कार (3 पुरस्कार, तकनीकी, प्रशासनिक और सहायता अनुवर्ग प्रत्येक में एक)	2014	प्रत्येक को रु. 51000/-
2) हलधर ऑर्गेनिक किसान पुरस्कार (1)	2015	रु. 1,00,000/-
3) पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार (1 राष्ट्रीय और 11 क्षेत्रीय पुरस्कार)	2016	राष्ट्रीय : रु. 1,00,000/- क्षेत्रीय रु. 51,000/- प्रत्येक
4) पंडित दीनदयाल राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार (1 राष्ट्रीय और 11 क्षेत्रीय पुरस्कार)	2016	राष्ट्रीय : रु. 25,00,000/- क्षेत्रीय : रु. 2,25,000/- प्रत्येक

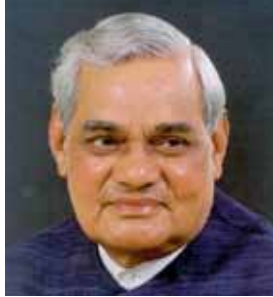
पं. दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना

- ◆ 32 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में जैविक कृषि/प्राकृतिक कृषि और गाय आधारित अर्थ-व्यवस्था पर 130 प्रशिक्षण कार्यक्रम
- ◆ रु. 5.35 करोड़ के बजट के साथ 100 केन्द्रों का निर्धारण
- ◆ 5 क्षेत्रीय कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन (लखनऊ, कोलापुर, अविकानगर, अमृतसर और झांसी)



राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस

प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की याद में 3 दिसंबर को राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस घोषित किया गया।



जय किसान—जय विज्ञान सप्ताह

पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी एवं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर 23 से 29 दिसंबर तक जय किसान – जय विज्ञान सप्ताह 2015 से सम्पूर्ण देश में मनाया जा रहा है।

राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना

- ◆ यूएस डॉलर 165.0 मिलियन (रुपये 1000 करोड़) के व्यय के साथ प्रस्तावित
- ◆ विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा 50:50 लागत हिस्सेदारी—आधार पर पोषित
- ◆ योजना की अवधि: छः वर्ष (2016–17 से 2021–22 तक)
- ◆ संबंधित विभागों में ईएफसी परिचालित किया गया

2016: अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष

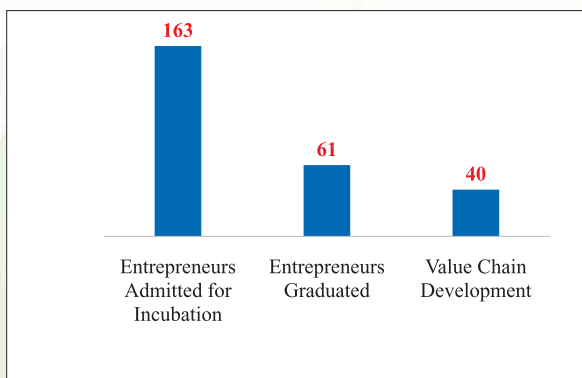
आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एनएफएसएम के अंतर्गत आरंभ किए गए दालों से संबंधित नए कार्यक्रम



- ◆ दलहन के गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए 150 “दलहन से संबंधित सीड-हब” की स्थापना
- ◆ वर्ष 2016–17 तक कम से कम 3717 क्विंटल और वर्ष 2018–19 तक 5801 क्विंटल तक अतिरिक्त प्रजनक बीज का उत्पादन
- ◆ 24 केन्द्रों पर जैव-उर्वरक तथा जैव नियंत्रण एजेंट के उत्पादन और आपूर्ति इकाइयों को सुदृढ़ करना

आईसीएआर में कृषि-व्यवसाय

25 कृषि-व्यवसाय ऊष्मायन (एबीआई) केन्द्रों की स्थापना (2015–16)



विषय क्षेत्र

पशु विज्ञान:	5
फसल विज्ञान:	4
कृषि इंजीनियरिंग:	4
कृषि शिक्षा:	2
बागवानी:	5
मत्स्य पालन:	4
एनआरएम:	1

नये आईसीटी ऐप और पोर्टल

- ◆ पूसा कृषि-प्रौद्योगिकी मोबाइल ऐप
- ◆ मोबाइल ऐप "riceXpert"
- ◆ ई-कपास नेटवर्क और प्रौद्योगिकी दस्तावेजीकरण
- ◆ नाशीजीवों और रोगों के लिए पल्सएक्सपर्ट
- ◆ बागवानी फसलों के लिए ई-पेस्ट सर्विलेंस और परामर्शी प्रणाली
- ◆ ऑन लाइन नाशीजीव निगरानी एवं परामर्शी सेवाएं
- ◆ नाशीजीव पूर्व चेतावनी अनुप्रयोग
- ◆ कृषि-डिजिटल डाटा पोर्टल
- ◆ बकरियों के उत्पादन एवं प्रबंधन पर जीएमआईएस



PulsExpert
Expert System For Pulse Crops

कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा नई पहलें

- ◆ वेब पोर्टल-कृषि विज्ञान केन्द्र नॉलेज नेटवर्क
- ◆ एम किसान पोर्टल- कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा 90 लाख किसानों को परामर्शी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं
- ◆ 100 कृषि विज्ञान केन्द्रों पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा स्वाचालित मौसम केन्द्रों की स्थापना
- ◆ 121 (2015-16 की 21 को सम्मिलित करते हुए) कृषि विज्ञान केन्द्रों पर जलवायु अनुकूलन पहलें
- ◆ चारा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन से संबंधित राष्ट्रीय पहल (एनआईएफटीडी)-100 केवीके

रोग का पूर्वानुमान

ब्रूसेल्लोसिस के निदान हेतु पारिर्विक प्रवाह आमापन

राष्ट्रीय पशु रोग रेफरल विशेषज्ञ प्रणाली (एनएडीआरईएस)

15 महत्वपूर्ण पशु रोगों का पुर्वानुमान लगाना/पूर्व चेतावनी देना



सहयोग

- ◆ आईसीएआर- आईसीएमआर के साथ एमओयू के क्षेत्र – (जूनोटिक रोग, एंटीमाइक्रोबायल प्रतिरोधक-पोषण एवं नाशीजीवनाशक प्रतिरोधक)
- ◆ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईएलआरआई, सीडीसी और एमएसयू एवं बीएमजीएफ, यूएसए)



गुड़ उत्पादन में उद्यमिता विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम

- ◆ इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिन क्षेत्रों में चीनी मिलें बंद हो गई है वहाँ के गन्ना किसानों को वैकल्पिक आय का स्रोत उपलब्ध कराया जाए जिससे चीनी मिल बंद होने के कारण गन्ना खेती से मोह भंग ना हो।
- ◆ दिनांक 05 मार्च 2016 को माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार श्री राधा मोहन सिंह जी द्वारा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र, मोतीपुर में गुड़ प्रशिक्षण इकाई का उद्घाटन तथा कृषक प्रशिक्षण भवन का शिलान्यास किया गया।
- ◆ माननीय मंत्री जी ने किसानों को संबोधित करते हुये कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण बहुत आवश्यक है और इस दिशा में मोतीपुर केंद्र में गुड़ इकाई की शुरुआत होना इस क्षेत्र के गन्ना किसानों के लिए वरदान साबित होगा।



रूपरेखा एवं मुद्रण

: मैसर्स रॉयल ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-89/1 नारायणा इण्डस्ट्रियल
एरिया, फेस-1, नई दिल्ली 110 028



कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

वेबसाइट: <http://agriculture.gov.in>